

हरित विकास, निवेश और रोजगार... इसी दिशा में आगे बढ़ रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी कंपनी प्रतिनिधियों को दिये प्रशस्ति-पत्र

- नीमच बन रहा ग्रीन पावर का ग्लोबल कैपिटल
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने किया नीमच एवं शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण



यदव एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने 1,553.98 करोड़ रुपये की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का भी भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 550 मेगावॉट क्षमता वाला आगर सोलर पार्क भी निमागधीन है, जिसकी इकाइयों के लिए 2.44 और 2.45 रुपये प्रति यूनिट की दरें प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद मध्यप्रदेश देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का हरित विकास हमारा लक्ष्य है। हरित विकास के जरिए प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में निवेश लाने और इसके जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अब स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा से इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश के नए औद्योगिक ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहे हैं। नीमच न केवल मध्यप्रदेश का, बल्कि ग्रीन पावर सेक्टर का ग्लोबल कैपिटल बन रहा है। उन्होंने बताया कि यहां देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज बन रहा है। नीमच जिले में कुल 675 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं कार्यशील हैं और लगभग 1 हजार 952 से अधिक मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।

113 जातियां आरक्षण सूची से बाहर



कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए इन विधेयकों के पक्ष में 186 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 17 सदस्यों ने विरोध किया और छह विधायक मतदान से अनुपस्थित रहे। नए कानून लागू होने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था में व्यापक बदलाव होंगे। इसके तहत आरक्षण का ढांचा 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, साथ ही ओबीसी श्रेणियों का भी पुनर्गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री गौरिशंकर घोष ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज (एससी-एसटी को छोड़कर) रिजर्वेशन ऑफ वैंकेंसी इन सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट बिल, 2026 और पश्चिम बंगाल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किए। विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का यह कदम पूरी तरह कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और इसका किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि बिना किसी फोल्ड सर्वे के ओबीसी सूची में शामिल की गई 113 श्रेणियों को हटाया गया है, जबकि विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर शामिल की गई 66 उप-श्रेणियों को बरकरार रखा गया है। आयोग तय करेगा नई सिफारिशें सरकार के अनुसार, संशोधित कानून के तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करेगा। यदि आयोग किसी समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा, तभी राज्य सरकार उस पर फैसला ले सकेगी। साथ ही, आयोग से परामर्श के बाद अलग-अलग ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी तय किया जाएगा। दूसरे संशोधन के जरिए आयोग की संरचना, अधिकार और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।

दिल्ली में आज से एसआईआर



नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की पूरी जानकारी साझा की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 13,000 से बीएलओ राजधानी भर में घर-घर जाकर 1.45 करोड़ वोटर्स (मतदाताओं) का सत्यापन करेगा। 17 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हर मौजूदा मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रेषण दिया जाएगा। मतदाता को एक भरा हुआ फॉर्म बीएलओ को जमा करना होगा और उसकी रसीद लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर घर बंद मिलता है तो बीएलओ कम से कम 3 बार वहां जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) प्रकाशित किया जाएगा। वहीं 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही 3 अक्टूबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।

आम बीनने गए दो बच्चों समेत तीन की आकाशीय बिजली से मौत

पेड़ के नीचे खड़े थे तीनों

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डुमकी में सोमवार शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार डुमकी निवासी रामसाय पिता तिरकु (36) सोमवार शाम करीब चार बजे गांव के प्राथमिक शाला के पास मवेशी चरा रहा था। उसी दौरान तेज हवा चलने लगी। हवा से पास के आम पेड़ से आम गिरने की संभावना पर नजदीक के घर में रहने वाला राजनाथ का पांच वर्षीय पुत्र सागर वहां पहुंच गया। इसी बीच घर समुपे चौरा निवासी मोहरसाय की नौ वर्षीय बेटा कुमारी रानी भी आम बीनने आ गईं। वह डुमकी में रिश्तेदारों के यहां आई हुई थीं। दोनों बच्चे आम बीन रहे थे और रामसाय मवेशी संभाल रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए तीनों आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और तीनों उसकी चपेट में आ गए।

जेल भेजे गए राम मंदिर के आठ चढ़ावा चोर

14 दिन की न्यायिक हिरासत

अयोध्या। दुनिया भर में रामभक्तों की आस्था को आघात पहुंचाने वाले राममंदिर चढ़ावा चोरों के आठों आरोपितों की पुलिस को रिमांड नहीं मिली। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई और आठों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इन आठों को पुलिस ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश भृगुचर निवारण जज रजत वर्मा ने 13 जुलाई तक आठों आरोपितों की न्यायिक रिमांड अर्थात् बढ़ा दी है। अयोध्या में अधिवक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने दो पुलिस ने किसी भी आरोपी की कस्टडी रिमांड की मांग अदालत से नहीं की। ऐसे में आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ नहीं होगी और वे न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों और जांच की प्रगति के आधार पर होगी। यह मामला प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरों के मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर रमाशंकर यादव टिबू सहित आठ लोगों के खिलाफ गुरुवार को आठ नामजद व एक अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ रामजन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया

6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो, वे विकास नहीं, स्वार्थ के लिए गए

धाराशिव/परभणी। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बागी 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा, 'अगर देश में कानून का राज है तो इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। ये सांसद विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए गए हैं।' उद्धव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर बीजेपी का बाबर जनता पार्टी बताया। उन्होंने कहा, 'बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। अब बाबर जनता पार्टी नए बने राम मंदिर को लूट रही है। दोनों में क्या फर्क है?'

उद्धव इन दिनों मराठवाड़ा के दौरे पर हैं। बाकी सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने परभणी और धाराशिव में अलग-अलग सभाओं को संबोधित किया। ठाकरे बोले- वे महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता खत्म करना चाहते हैं: धाराशिव में उद्धव ने कहा, अगर आपके पास पहले से बहुमत है, तो फिर मेरे सांसदों की जरूरत क्यों पड़े? यह सिर्फ बग़ावत नहीं, बड़ा राजनीतिक खेल है। वे महाराष्ट्र, शिवसेना और महाराष्ट्र धर्म को खत्म करना चाहते हैं।

भारत की साख पर नहीं कोई आंच, मूडीज को पूरा कॉन्फिडेंस

खतरे में भी खड़े होने का दम

नई दिल्ली। भारत की साख पर आंच आने का कोई खतरा नहीं है। मूडीज रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जाहिर किया है। उसके अनुसार, भारत इस साल अपनी इन्वेस्टमेंट-ग्रेड सॉल्वेंसी रेटिंग को जोखिम में डाले बिना मौजूदा अनुमानों से ज्यादा राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) को संभालने की अच्छी स्थिति में है। मूडीज का मानना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बजट पर पड़ने वाला कोई भी दबाव अस्थायी हो सकता है। आसान शब्दों में जब सरकार की कमाई कम और खर्च ज्यादा होता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जोर्ज लेना पड़ता है, उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसलिए बढ़ गई टेंशन: इस साल मिडिल इस्ट में संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद देश के राजकोषीय हालात (फिस्कल आउटलुक) को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। तेल की ऊंची कीमतें आमतौर पर भारत के आयात बिल को बढ़ाती हैं। महंगाई का दबाव बढ़ता है। सक्विडी की लागत में इजाफा होता है। इससे आर्थिक विकास और सरकार की राजकोषीय स्थिति दोनों के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर स्थित मूडीज रेटिंग्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन डी गुजमैन ने कहा कि हम नहीं लगाता कि भारत पर इसका कोई खास असर पड़ेगा क्योंकि यह झटका ज्यादातर देशों के लिए निगेटिव है। मूडीज ने अभी भारत को बीएएफ 3 रेटिंग दी है। यह इन्वेस्टमेंट-ग्रेड कैटेगरी में सबसे निचला स्तर है।

रेप-नर्द के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की बच्चों से रेप और हत्या करने के आरोपी 65 साल के दोषी भीमराव कांबले को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 60 दिन बाद आया है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताने हुए कहा कि आरोपी का कृत्य बेहद क्रूर, अमानवीय और बर्बर था। सोमवार सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया गया था। कांबले पेशे से मजदूर हैं। वह 7 बच्चों का पिता और 11 बच्चों के दादा हैं। यह घटना 1 मई को पुणे जिले के नसरपुर गांव में हुई थी। बच्चों गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई हुई थीं। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कांबले ने उसे खाने-पीने की चीजें और गाय का नवजात बछड़ा दिखाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह उसे मर्विशियों के तबले के पास बने एक शेड में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ रेप किया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

असुरक्षा मध्य प्रदेश में 253 पुल जर्जर, 46 जानलेवा

पुराने ही नहीं नए पुल भी बीमार, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

अंशुमन खरे

भोपाल। मध्य प्रदेश में सड़कों पर सुरक्षित सफर का दावा एक बार फिर सवालियों के घेरे में है। प्रदेश में 253 पुलों को जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनकी सुरक्षा जांच यानी ब्रिज ऑडिट की प्रक्रिया तय समय सीमा के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। इनमें से 46 पुलों की स्थिति बेहद खतरनाक श्रेणी में बताई गई है, जहां कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलों की जांच को लेकर पहले से स्पष्ट नियम मौजूद हैं। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने भी पुलों और पुलियों की नियमित जांच को अनिवार्य किया है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) और मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के अनुसार हर साल 15 जून तक प्रदेश के सभी पुलों और पुलियों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जाना जरूरी है। इस जांच में पुल की नींव, पिलर, बियरिंग्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, स्लैब की स्थिति और जल निकासी व्यवस्था को बारीकी से जांच की जाती है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर जियो-टेक तकनीकों के साथ विभागीय रिपोर्ट करनी होती है, जबकि बड़े पुलों का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (ईई) स्तर के अधिकारी करते हैं। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई जगहों से जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है।

विवरण	आंकड़े / जानकारी
कुल जर्जर पुल	253
बेहद खतरनाक पुल	46
विशेष मजबूतीकरण के लिए बजट	11.41
करोड़ रुपए (मार्च 2026 में स्वीकृत)	
बजट के तहत कवर होने वाले पुलों की संख्या	50
संवेदनशील पुल	
सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका	ग्वालियर संभाग (22 पुल)

अकाल तख्त का आदेश- 1 महीने में बेअदबी कानून संशोधित करो

आप विधायकों ने कबूला, बिना पढ़े साइन किए, जथेदार ने सीएम मान के 2 वीडियो दिखाए

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बेअदबी कानून जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सक्ता (संशोधन) एक्ट-2026 में एक महीने में संशोधन करने का आदेश दिया है। सोमवार (29 जून) को हुई सुनवाई के दौरान अकाल तख्त जथेदार कुलदीप सिंह गड़गाज ने कानून पर 6 एतराज जताए। उन्होंने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए। जथेदार ने 2 सवाल पूछे। इस दौरान विधायकों ने माना कि कानून को बिना पढ़े सहमत दी। सुनवाई से पहले जथेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दो वीडियो भी सुनवाई पेशी के लिए आप के सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर लिखित स्पष्टीकरण के साथ अकाल तख्त पहुंचे। कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय विधायक भी सुनवाई में मौजूद रहे। पहला सवाल: अकाल तख्त जथेदार कुलदीप सिंह गड़गाज ने सीएम भगवंत मान के 2 बयान सुनवाए। जिनमें वह कह रहे हैं कि अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके मां-बाप या कस्टोडियन को सजा मिलेगी। उन्होंने आप मंत्री-विधायकों से पूछा कि क्या ये बात कानून में लिखी है। कृषि मंत्री गुरमोत खड्डियां कोई स्पष्ट बात नहीं कर सके। इस पर विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कहा कि इस सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, यह संवेदनशील है। इस पर अकाल तख्त जथेदार ने कहा कि सीएम ने ही हर कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट करने को कहा था। इसके लिए अकाल तख्त को ललकारा भी था।

सरपंच के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बागरी के ग्रामीण और किसान पहुंचे कलेक्टर

अतिक्रमण हटाने और शासकीय रास्ता खुलवाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

आज की जनधारा

विदिशा। सोमवार को ग्राम बागरी निवासी ग्रामीण और किसान बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि शासकीय रास्ते पर कुछ किसानों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चा कर लिया गया है। जिसके चलते आगे के किसानों को जाने-आने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान सरपंच राहुल गुजर, निरंजन सिंह, विजय सिंह, रेवारा, भीमक सिंह, हर्ष, गब्बर सिंह, मनोज, पूरन सिंह ने बताया कि खेतों पर जाने वाले रास्ते पर आगे के किसानों द्वारा कच्चा कर खेती की जा



रही है और अन्य किसानों को अपने खेतों पर जाने से रोका जा रहा है। जब किसान अपने ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाते हैं तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा खेत सड़क का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन आगे के

किसानों द्वारा निर्माण कार्य को रकवा दिया गया है। जिसके कारण से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तहसीलदार, एमडीएम को भी आवेदन दे चुके हैं और सरकारी रास्ते का सीमांकन

करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मॉके पर जाकर सीमांकन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शासकीय रास्ते का सीमांकन कराया जाए और जिन किसानों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चा किया हुआ है उसे हटवाया जाए।

जिसके कारण रास्ता रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद ही सड़क का निर्माण आगे हो पाएगा। ऐसे में किसानों के लिए आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क न होने के कारण कौचड में से ट्रैक्टर निकालकर ले जाते हैं जिसमें कई बार ट्रैक्टर फंस जाते हैं और उन्हें निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सड़क का निर्माण हो जाएगा तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों द्वारा शासकीय रास्ते पर कच्चा किया हुआ है उन्हें हटवाया जाए और रास्ते को खुलवाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे।

साइबर ठगी को रोकने पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान



आज की जनधारा

विदिशा। साइबर के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत गांव-गांव और चौक-चौराहों पर लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों में बच्चों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवाना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में संचालित 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के पांचवें दिवस

जिलेभर में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के अंतर्गत लगभग 9000 नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 को जानकारी देकर जागरूक किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बीजामंडल पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों एवं नागरिकों को साइबर फ्राड से बचाव तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करने के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं थाना लटेरी पुलिस द्वारा आयोजित चौपाल में

नागरिकों को बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाता विवरण, एटीएम पिन, पासवर्ड आदि सांझा न करें। सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी ऑफर, नौकरी के झांसे, संदिग्ध लिंक तथा अज्ञात एप डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी गई। विदिशा पुलिस द्वारा नागरिकों से अतीत की गई कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, लिंक अथवा ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्कता बरतें। यदि किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

आईटीआई में हुआ नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक संस्था अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति सहित परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल प्राइवेट आईटीआई में नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले को नशा मुक्ति करने हेतु 150 से अधिक विद्यार्थी नशे के खिलाफ एक सामाजिक जन जागरण युद्ध लड़ेंगे। यह बात नशा मुक्ति भारत अभियान के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर और मुख्य कला वेद प्रकाश शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नशे जैसी सामाजिक बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए एक



युद्ध नशे के विरुद्ध जैसे अभियान की आवश्यकता है। इस अभियान को जिले के विद्यार्थी सामूहिक रूप से आगे आकर लड़ेंगे। जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ अश्व विहारी खरे ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसको समाप्त करने हेतु समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर एक सामाजिक आंदोलन बनकर निरन्तर काम करना होगा। प्रजापिता

ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सपना दीदी ने कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए नशा मुक्ति की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और अभियान की गति को बनाए रखने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मालती लोधी और सामाजिक न्याय विभाग के नितिन दुबे विशेष रूप से उदात्त रहे।

एक नई चेतना और ऊर्जा का विकास होगा। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और अभियान की गति को बनाए रखने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मालती लोधी और सामाजिक न्याय विभाग के नितिन दुबे विशेष रूप से उदात्त रहे।

ग्राम सुआखेड़ी में नवीन विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत

आज की जनधारा

विदिशा। ग्राम सुआखेड़ी में 33/11 केवी क्षमता के 5 एम्पीए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन के अग्रह एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा पर मिली है। इस परियोजना के तहत 1.5 किलोमीटर 33 केवी लाइन तथा 14 किलोमीटर 11 केवी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुल 248.15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नवीन विद्युत सब स्टेशन के निर्माण से सुआखेड़ी सहित आसपास के अनेक गांवों को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर विधायक मुकेश टंडन ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र को बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कांग्रेस सेवा दल ने निकाली प्रभात फेरी, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता का दिया संदेश



आज की जनधारा

विदिशा। कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में माधवगंज चौबे से प्रातःकाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी कांग्रेस पार्टी का ध्वज धामे आगे चल रहे थे, उनके साथ सेवा दल के पदाधिकारियों हाथ में डोलक मंत्रियों के साथ देश प्रेम से ओत प्रोत गीत गाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों का घ्रण्य किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष

मोहित रघुवंशी ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल की पहचान अनुशासन, सेवा और राष्ट्र निष्ठा से है, प्रभात फेरी के माध्यम से देशभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक एकता के संदेश देने का प्रयास किया है। जिला कांग्रेस सेवा दल मुख्य संगठक रामराज सिंह दांगी ने कहा कि समाज में सकारात्मक सोच, आपसी सौहार्द और जनजागरूकता फैलाना सेवा दल का प्रमुख उद्देश्य है। जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील शर्मा ने बताया की

प्रभात फेरी के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रसेवा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करना है। अंत में जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रगान के साथ प्रभात फेरी का समापन किया गया। इस दौरान पर्वत सिंह गौड़, ब्रजेंद्र वर्मा, जाजू पाल, कामल जाट, जवाहर कुशवाहा, राजेश रघुवंशी, शैलेन्द्र दांगी, पवन पचौरी, दरभत सिंह, नीरज रघुवंशी, बलराम दांगी, आदित्य जैन, राकेश दांगी, शिवम मीणा, आलोक आदि मौजूद थे।

रैकवार समाज के दो परिवारों में हुई मारपीट

आज की जनधारा

विदिशा। 26 तारीख की रात में कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहनगिरी मां अस्पताल के पास रहने वाले रैकवार परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के घायल जिला अस्पताल में भर्ती है। उनका आरोप है कि पास में रहने वाले ओम प्रकाश रैकवार और उनके परिवार के अन्य लोग जो विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं और नशे का कारोबार भी करते हैं, वह घर पर आए और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। महिलाओं, बच्चों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। कोतवाली थाने द्वारा घटना के बाद 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई न होने का आरोप भी परिवारों द्वारा लगाया गया है। यह बात भी सामने आई की दोनों परिवारों का पुराना विवाद है, इसी रंजिश के चलते यह मारपीट की गई है।

एसएटीआई में चल रहे एनसीसी कैंप का हुआ समापन



आज की जनधारा

विदिशा। 14 एमपी बदालिन एनसीसी विदिशा के कमान अधिकारी कर्नल अशुभान सिंह के मार्गदर्शन एवं लेफ्टिनेंट कर्नल सनी वैद्य के नेतृत्व में एसएटीआई डिग्री कॉलेज में चल रहे 10 दिवसीय सीपीटीसी कैंप-9 का समापन हुआ। कैंप के दौरान कैडेट्स द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, फायरिंग, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां एकल नृत्य, समूह नृत्य, कविताएं, वासुदेव वादन जैसी खूबसूरत प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैडेट्स ने प्रथम, द्वितीय स्थान आने पर पुरस्कार प्राप्त किया। क्वॉजिंग एंडेस को संबोधित करते हुए कमान अधिकारी कर्नल अशुभान सिंह द्वारा कैंप का महत्व समझाया। एनसीसी ए. बी. एवं सी. सीटीफिकेट की अहमियत बताई।

एनसीसी ए. बी. एवं सी. सीटीफिकेट परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए उसकी रणनीति बताई। कमान अधिकारी ने कैडेट्स को यह भी बताया कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार रहना होता है, अपने आपको कैसे मजबूत बनाए जाए। लक्ष्मीकांत मरखेडकर ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है बस उसे पहचान कर मौका देने की आवश्यकता है और एनसीसी उसे उचित मंच प्रदान करती है। कैंप के दौरान प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सनी वैद्य भी मौजूद रहे और कैडेट्स को प्रोत्साहित किया। कमान अधिकारी ने सभी एनसीसी कैडेट के साथ सभी एनसीसी अधिकारियों, सूबेदार मेजर हृदय रंजन एवं पी.स्टाफ को सफल आयोजन पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। एनसीसी गान के साथ कैंप से सभी ने विदा ली।

दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण एवं सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर का आयोजन विदिशा में आज

आज की जनधारा

विदिशा। भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को लाभांशित करने तथा उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदिशा के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आज 30 जून को शिविर आयोजित किया गया है। यह शिविर पूर्वाहन 11 बजे से शुरू होगा। जिला पंचायत (सामाजिक न्याय विभाग) विदिशा द्वारा संबोधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित एडीआईपी योजना के तहत ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं तथा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु जिन लाभार्थियों को पांच वर्ष पूर्व सहायता मिली थी, उन्हें पुनः पात्रता के आधार पर लाभांशित किया जाएगा। शिविरों में दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा। इनमें व्हील चेयर, बैसचीर, ट्राइ साइकिल, मोटराइज्ड ट्राइ साइकिल, श्रवण यंत्र, कुत्रिम अंग, एल्बो स्टिक, वॉकर, स्मार्ट केन तथा अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य शिविर में पंजीयन एवं चिन्हांकन के लिए दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार के फोटो तथा आय प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संयुक्त निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए



आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अशुल गुप्ता के निर्देशन में रविवार को प्रखर सोनोग्राफी सेंटर के पीछे स्थित पुराना हॉस्पिटल रोड पर संचालित क्लिंकिट स्टोर्स का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व विभाग तथा नापतोल विभाग के अधिकारियों ने स्टोर्स में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मानकों का परीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य

उत्पादों के नमूने एकत्रित किए गए। इनमें अमूल बफेलो मिल्क, अमूल टॉड मिल्क, अमूल लस्सी शुगर फ्री, फॉरच्यून ब्रांड का वेसन तथा फॉरच्यून ब्रांड की सूजी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि एकत्रित सभी नमूनों को आवश्यक परीक्षण एवं गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। निरीक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्रियों उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन

सुनिश्चित करना है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नमूनों की गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह संयुक्त कार्रवाई डिप्टी कलेक्टर श्री मोतीलाल अहिरवार की निगरानी में संपादित की गई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिए इस प्रकार के निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आज पेंशनर्स निकालेंगे रैली, देंगे ज्ञापन

आज की जनधारा

विदिशा। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश की जिला इकाई विदिशा की आवश्यक बैठक रविवार को श्री हरि वृद्धाश्रम के शांत एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश स्थायी आंदोलन के दूसरे चरण को प्रभावी और सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। बैठक में पेंशनर्स हितों से संबंधित छह सूत्रीय लंबित मांगों पर गंभीर मंथन किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 30 जून मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर परिसर में विशाल पेंशनर्स रैली एवं सभा आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों के त्वरित निराकरण की पुरजोर मांग की जाएगी। यह संयुक्त कार्रवाई डिप्टी कलेक्टर श्री मोतीलाल अहिरवार की निगरानी में संपादित की गई। पेंशनर्स केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवनभर की निष्ठापूर्ण सेवाओं का सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। अतः पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। उन्होंने शासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और अधिकारों को रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह

किया। उद्देशनीय है कि रिगिडिफ फुहारों के बीच भी पेंशनर्स प्रतिनिधियों का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ। वर्षों की बूढ़ों के बीच एकत्रित वरिष्ठजन संगठनात्मक एकता, संघर्षशीलता और अटूट विश्वास का प्रेक उदाहरण प्रस्तुत करते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर अपने अधिकारों की प्राप्ति का संकल्प और सामूहिक शक्ति का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। बैठक को संबोधित करते हुए पेंशनर्स जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति के बल पर पेंशनर्स अपनी न्यायसंगत मांगों को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। उन्होंने सभी साथियों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को ऐतिहासिक सफलता प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का या वह कानूनी, बल्कि एक सभी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों का है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल समाज और शासन की सेवा में समर्पित किया है। सामूहिक संकल्प, अनुशासित संगठन और सशक्त आवाज के माध्यम से ही पेंशनर्स हितों की विजय का मार्ग प्रशस्त होगा।

समीक्षा

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण पर कलेक्टर सख्त

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अशुल गुप्ता ने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों तथा जिले में संचालित विभिन्न विशेष अभियानों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समय-समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि एल-1 स्तर पर लंबित एवं नॉन-अटेंडेड शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत शिकायतों



का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद भी शिकायतें नॉन-अटेंडेड श्रेणी में पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन कटौती सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में आगामी पौधरोपण अभियान की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पौधरोपण के लिए आवश्यक पौधों की व्यवस्था वन विभाग तथा उद्यानिकी

विभाग की नर्सरियों से हो की जाए। उन्होंने विभागवार पौधरोपण के लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि पौधरोपण से पूर्व सभी विभाग यह

जाणकारी अंकुर एवं वायुदूत पोर्टल पर दर्ज करें कि पौधे किस स्थान पर लगाए जाएंगे। इसके पश्चात पौधरोपण की अद्यतन स्थिति, जियो टैग फोटोग्राफ्स सहित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गत वर्ष लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति का उद्देश्य विशेष रूप से रिमार्क कॉलम में किया जाए, ताकि पौधों के संरक्षण और जीवित रहने की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

जाणकारी अंकुर एवं वायुदूत पोर्टल पर दर्ज करें कि पौधे किस स्थान पर लगाए जाएंगे। इसके पश्चात पौधरोपण की अद्यतन स्थिति, जियो टैग फोटोग्राफ्स सहित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गत वर्ष लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति का उद्देश्य विशेष रूप से रिमार्क कॉलम में किया जाए, ताकि पौधों के संरक्षण और जीवित रहने की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

कृषक भारती कॉ-ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा सहकारिता सशक्तिकरण अभियान का आयोजन



आज की जनधारा

विदिशा। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृषक) विदिशा द्वारा गुलाबगंज बैंक शाखा के सहकारिता सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सहकारिता

क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं की भूमिका तथा भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ध्रुव कुमार शर्मा डीआरसीएस, विदिशा कैलाश यादव सर्फिल ऑफिसर

(सहकारिता), ग्यारस सहकारिता कुमार अहिरवार सहकारिता निरीक्षक, गुलाबगंज क्षेत्र माधो सिंह ठाकुर शाखा प्रबंधक, गुलाबगंज बैंक शाखा वृजेश शर्मा बैंक पर्यवेक्षक, गुलाबगंज शिवराज ठाकुर प्रबंधक आदि मौजूद रहे।

भोपाल में भू-माफियाओं पर आसमान से नजर

सैटेलाइट से होगी सरकारी जमीन की लाइव मॉनिटरिंग

भोपाल। राजधानी भोपाल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी जमीनों की सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी। जैसे ही किसी सरकारी भूमि पर नया अतिक्रमण या अवैध निर्माण शुरू होगा, उसकी डिजिटल सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंच जाएगी और मौके पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के सभी एसडीएम को सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए कलेक्टरों में एक विशेष राजस्व सेल बनाया जाएगा, जो सैटेलाइट इमेज के आधार पर सरकारी जमीनों पर नजर रखेगा। सैटेलाइट से अलर्ट मिलने के बाद संबंधित पटवारी मौके का सत्यापन करेगा और उसके बाद एसडीएम व तहसीलदार की टीम तत्काल अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगी। पुराने कब्जों पर भी चलेगा अभियान- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि



कार्रवाई केवल नए अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहेगी। पहले से सरकारी जमीनों पर किए गए पुराने अवैध कब्जों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वहीं सरकारी जमीन पर बसी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए नियमानुसार दूसरी जगह शिफ्ट करने की

योजना भी तैयार की जा रही है। 32 हजार एकड़ का डिजिटल लैंड बैंक तैयार जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों का करीब 32 हजार एकड़ का डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया है। इनमें लगभग 22,420 एकड़ ऐसी भूमि है, जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ से

डीजीपीएस से होगा सीमांकन, फिर लगेगी फेंसिंग

सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने के लिए अब अत्याधुनिक डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जिन शासकीय भूमि पर स्वामित्व को लेकर विवाद है या जिन पर निजी व्यक्तियों द्वारा दावे किए जा रहे हैं, उनका डीजीपीएस के माध्यम से सटीक डिजिटल सीमांकन कराया जाएगा। इससे जमीन की वास्तविक सीमा का निर्धारण पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ हो सकेगा। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महत्वपूर्ण सरकारी जमीनों के चारों ओर लोहे की तारबंदी (फेंसिंग) कर उन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित किया जाएगा। इससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाएं कम होंगी और विवादित भूमि को स्पष्ट पहचान सुनिश्चित होगी। राजस्व विभाग डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सीमाओं का सत्यापन करेगा, जिससे भूमि संबंधी विवादों के त्वरित समाधान में भी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी जमीनों पर शुरूआती स्तर पर ही अवैध कब्जों को रोकना, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि डीजीपीएस तकनीक अपनाने से सीमांकन की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनेगी। इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य में भूमि प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

अधिक है, जबकि करीब 9,580 एकड़ भूमि एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली है। इस डिजिटल रिकॉर्ड और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से पटवारियों को बार-बार मौके पर निरीक्षण

करने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही सरकारी परियोजनाओं और संस्थाओं के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी तेज और अधिक पारदर्शी हो सकेगी।

सड़क हादसों में गोल्डन ऑवर फोकस

भोपाल। सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों के मामलों में मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे अहम माने जाने वाले गोल्डन ऑवर को ध्यान में रखते हुए एम्स भोपाल 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक एडवॉन्स टॉमा लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर कोर्स आयोजित करेगा। इस प्रशिक्षण में डॉक्टरों को गंभीर रूप से घायल मरीजों के त्वरित आकलन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपचार की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। आपातकालीन इलाज की गुणवत्ता होगी बेहतर यह प्रशिक्षण अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के प्रमाणित एटीएलएस इंडिया कार्यक्रम के तहत होगा। इसमें सड़क हादसों, उंचाई से गिरने, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर चोटों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मरीजों को मिलेगा सीधा फायदा एम्स के अनुसार प्रशिक्षित डॉक्टर गंभीर मरीजों की स्थिति का तेजी से आकलन कर सही समय पर जीवनरक्षक उपचार दे सकेंगे। इससे दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने और उन्हें जल्दी स्वस्थ करने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही अस्पतालों में टॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

अब चुस्त-दुरुस्त नजर आएंगे मध्यप्रदेश जीआरपी के जवान

मोटे पुलिसकर्मियों को फिट करने खुद ट्रैक पर उतरे एडीजी

भोपाल। पुलिस की पहचान सिर्फ वर्दी और अनुशासन से नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता और त्वरित कार्रवाई से भी होती है। बढ़ता मोटापा, अनियमित जीवनशैली और लगातार ड्यूटी के दबाव के कारण पुलिस बल के एक बड़े हिस्से की फिटनेस प्रभावित हो रही थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्यप्रदेश शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जीआरपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट बनाने के लिए विशेष फिटनेस अभियान की शुरुआत की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं एडीजी ट्रैक पर उतरकर जवानों के साथ दौड़ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी को अपने साथ दौड़ना देख जवानों का उत्साह भी बढ़ा है। अक्सर पुलिस महकमे में बढ़ती तौंद और खराब होती जीवनशैली के कारण पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एडीजी बाबू सिंह ने यह कड़ा और सुधारात्मक कदम उठाया है। इस नई पहल के तहत अब हर शनिवार को अनफिट और



अधिक वजन वाले पुलिसकर्मियों के लिए विशेष दौड़ और शारीरिक व्यायाम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की सबसे खास बात यह रही कि केवल मातहतों को निर्देश नहीं दिए गए, बल्कि जीआरपी के एड्रॉ राजा बाबू सिंह खुद पुलिसकर्मियों के साथ ट्रैक पर दौड़ लगाते नजर आए। कप्तान को अपने साथ दौड़ना देख पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ा। डिजिटल और फिजिकल फिटनेस पर जोर जीआरपी का यह अभियान केवल दौड़ तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों के अनुसार इसमें स्वास्थ्य जागरूकता, नियमित

फिटनेस मॉनिटरिंग और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा। भविष्य में डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से पुलिसकर्मियों की फिटनेस प्रगति पर भी नजर रखी जा सकती है। पुलिस विभागों में बढ़ रही फिटनेस की संस्कृति देश के कई राज्यों में पुलिस बल को अधिक फिट और प्रोफेशनल बनाने के लिए नियमित फिटनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश जीआरपी का यह अभियान भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि यह सफल रहता है तो भविष्य में अन्य पुलिस इकाइयों में भी इसे लागू किया जा सकता है।

मानसून के तीन सिस्टम एकसाथ सक्रिय

मध्य प्रदेश में बारिश पकड़ रही रफ्तार, भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश

मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।



हिस्से को कवर कर लिया है और अगले 48 घंटों में इसमें और तेजी देखी जा सकती है और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों को भी अगले दो से तीन दिनों में कवर सकता है। वहीं, कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से 29 जून को राजधानी भोपाल के साथ जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सीधी, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल और सागर के कुछ इलाकों में बारिश देखने मिल सकती है।

गर्मी से हल्की राहत, उमस रहेगी बरकरार

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश या लगातार कई घंटों तक बारिश नहीं हुई है, जिससे उमस-बार-बार लोट रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री

सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में लगातार बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आएगी।

देश में तीन वेदर सिस्टम सक्रिय

आईएमडी के मुताबिक देश में तीनों मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से देश के कई राज्यों और मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल सकता है। उत्तरी गुजरात के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गया है, इसकी वजह से हवा में तेजी से नमी आ रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं अचानक भारी बारिश भी हो सकती है।

मध्य प्रदेश को मिल सकती है राहत

दूसरा सिस्टम भी मध्य प्रदेश को छूकर गुजर रहा है। ये वेदर सिस्टम उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश से विदम्बं होते हुए तेलंगाना तक टूट लाइन बना रहा है। जिसकी वजह से उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी,

जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में अचानक तेज बारिश हो सकती है। अगर इस ट्रफ लाइन के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हुआ तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाती है। तीसरा वेदर सिस्टम भी मध्य प्रदेश पर प्रभाव डाल सकता है। दरअसल, तीसरा वेदर सिस्टम पंजाब से यूपी और बिहार को कवर कर रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर पड़ सकता है। इसकी वजह से ग्वालियर-चंबल, रीवा, रीवा आदि क्षेत्रों में गरज-चमक देखने मिल सकती है।

जुलाई से मिलने लगेगी राहत

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर अब इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो जुलाई की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देखने मिल सकती है। वहीं, तीन वेदर सिस्टम सक्रिय होने से पूर्वी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है।

ट्राइबल स्कूलों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित

भोपाल। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के शासकीय विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्कूलों में छात्र-छात्राएं उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन हजारों शिक्षकों के पद रिक्त होने से अध्यापन कार्य में परेशानी आ रही है। इस मामले को लेकर ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डीके सिंगोर ने जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए स्थानांतरण के कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी कम हो गई है। एसोसिएशन



का कहना है कि विभाग में नई नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में वर्तमान में संचालित एक शिक्षकीय विद्यालयों में स्कूल संचालन करना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ नए प्रवेश और नामांकन प्रक्रिया में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं।

एक जुलाई से दौड़ेगी कानपुर-मदुरै स्पेशल ट्रेन

भोपाल-इटारसी और बीना के यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

इस विशेष ट्रेन का सीधा लाभ पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी के यात्रियों को मिलेगा।



भोपाल। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 1 जुलाई से कानपुर सेंट्रल और मदुरै के बीच

साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस विशेष ट्रेन का सीधा लाभ पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी के यात्रियों को मिलेगा। इससे यात्रियों को बिना ट्रेन बदले

दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शहर मदुरै तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। पांच फेरे लगाएगी ट्रेन- रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 01925 कानपुर सेंट्रल-मदुरै स्पेशल प्रत्येक बुधवार 1 जुलाई

से 29 जुलाई तक कुल पांच फेरे लगाएगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सुबह 8:10 बजे रवाना होकर बीना दोपहर 3:40 बजे, भोपाल शाम 5:20 बजे और इटारसी शाम 7:25 बजे पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01926 मदुरै-कानपुर सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक शनिवार 4 जुलाई से 1 अगस्त तक पांच फेरे लगाएगी। वापसी में यह ट्रेन इटारसी दोपहर 3:05 बजे, भोपाल शाम 5:05 बजे, बीना रात 8:25 बजे और ललितपुर रात 9:13 बजे पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में झांसी, ललितपुर, नागपुर, बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा, नेल्लोर, रेणुगुंटा, कटपडी, सेलम, कन्नूर और डिंडोरी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी।

टिवषा शर्मा मौत केस में आज अहम सुनवाई

गिरिबाला सिंह ने मांगी कॉल डिटेल्स, बैंक रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट



भोपाल। शहर बहुचर्चित टिवषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को कोर्ट नए सिरे से सुनवाई करने जा रहा है। इस दौरान सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह के लंबित आवेदनों पर न्यायालय अपना निर्णय लेगा। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें 30 जून तक की मोहलत दी थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने अपने आवेदनों के माध्यम से टिवषा शर्मा के परिजनों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, बैंक खातों के स्टेटमेंट और घटना के वक्त कार से बरामद हुई चाबी की जानकारी देने का आग्रह किया गया है। माना जा रहा है कि इन साक्ष्यों के सामने आने से मामले को नई दिशा मिल सकती है। दूसरी ओर, पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अंकुर पांडे ने भी कोर्ट में एक

आवेदन प्रस्तुत कर टिवषा की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। इस विषय पर न्यायालय ने पूर्व में एम्स भोपाल और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। एम्स द्वारा समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने इस आवेदन पर भी सुनवाई के लिए 30 जून यानी मंगलवार की तारीख दी है। सीबीआई कर रही मामले की जांच हम बता दें कि भोपाल के बागमंगलिया स्थित ससुराल में रहने वाली टिवषा शर्मा की बीती 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद उन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस समय पूरी जांच का जिम्मा सीबीआई के पास है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार की सुनवाई अहम है, जिससे पिछले कुछ समय से सुस्त पड़ी इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच में तेजी आएगी और कई नए तथ्य उजागर होंगे।

प्रदेश में जुलाई से दौड़ेगी पीएम-ई बसें

इंदौर से शुरुआत, भोपाल और जबलपुर में भी शुरु होगी सेवा

भोपाल। मध्य प्रदेश में शहरी सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जुलाई से प्रदेश के प्रमुख शहरों में पीएम-ई बस सेवा शुरू होगी। पहले चरण में इसकी शुरुआत इंदौर से होगी, जबकि भोपाल और जबलपुर में भी 100-100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेगी। योजना के तहत पहले चरण में इंदौर के 9 रुटों पर 150 ई-बसें, भोपाल के 10 रुटों पर 100 ई-बसें और जबलपुर में 100 ई-बसें संचालित की जाएंगी। दूसरे चरण में ग्वालियर, सागर और उज्जैन को इस सेवा से जोड़ा जाएगा।



प्रदेश के छह शहरों में कुल 592 इलेक्ट्रिक बसें का संचालन किया जाएगा। डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक सुविधाएं ई-बसें के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी

प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। यात्रियों के लिए टिकटिंग की सुविधा चलो एप के माध्यम से उपलब्ध होगी। वातानुकूलित 32-सीटर इन बसें में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे

शहरी सफर अधिक आरामदायक और सुविधाजनक होगा। ग्रांस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर होगा संचालन पीएम-ई बस सेवा का संचालन ग्रांस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर किया जाएगा। कंपनी ड्राइवर, कंडक्टर और मेटेनेंस स्टाफ उपलब्ध कराएगी। संचालन के लिए कंपनी को 58.14 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान मिलेगा। इसमें 22 रुपये प्रति किलोमीटर केन्द्र सरकार सब्सिडी देगी, जबकि 36.14 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान राज्य सरकार करेगी। प्रत्येक बस के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 180 किलोमीटर संचालन अनिवार्य

होगा। छह शहरों में बनेंगे नौ आधुनिक डिपो ई-बसें के संचालन और रखरखाव के लिए छह शहरों में नौ आधुनिक डिपो विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में दो डिपो बनेंगे। इंदौर में नायता मंडला और चंदन नगर में दो डिपो तैयार किए जाएंगे। ग्वालियर में दो डिपो बनाए जाएंगे। उज्जैन, सागर और जबलपुर में एक-एक डिपो विकसित होगा। डिपो निर्माण की लागत में 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार अपने हिस्से के रूप में लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च

करेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा तैयार ई-बसें के लिए डिपो के साथ अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दो-दो, जबकि जबलपुर, सागर और उज्जैन में एक-एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन स्टेशनों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 41 किलोमीटर लंबी हाई-टेंशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार की सहायता से विशेष सब-स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक बसें का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके।

न्यूज | ड्रीफ

'स्कूल चले अभियान' के तहत वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ने पटेरा में बच्चों को पढ़ाया पर्यावरण का पाठ



दमोह। समग्र शिक्षा अभियान जिला दमोह के अंतर्गत कलेक्टर के आदेशानुसार 'स्कूल चले अभियान' चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ईश्वर जराडे ने शासकीय सीएम राइस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटेरा पहुंचकर छात्र-छात्राओं को स्कूल अभियान का पाठ पढ़ाया। डीएफओ ने बच्चों को वन विभाग से जुड़ी जरूरी जानकारियां दीं। उन्होंने पेड़-पौधों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं विशेष रूप से मौजूद रहे।

पल्स पोलियो अभियान 105740 बच्चे पोलियो से प्रतिरक्षित, मिली अतिरिक्त खुराक

दमोह। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के पहले दिवस 105740 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर प्रतिरक्षित किया गया। अभियान के अन्तर्गत 29 एवं 30 जून को छूटे हुए बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने स्वास्थ्य विभाग की टीम-घर-घर भ्रमण कर, मोबाइल एवं टूटित टीम के माध्यम से ऐसे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी जो किसी कारणवश पोलियो रोधी दवा पीने से छूटे गये हैं। आमजन की सुविधा के लिए बस स्टैंड, रेलेवे स्टेशन, हाट-घर, मेले एवं अन्य आवागमन वाले स्थानों पर टीम पोलियो की दवा से वंचित बच्चों की पहचान कर पोलियो की दवा पिलाने का कार्य किया जा रहा है।

पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे कलेक्टर प्रताप नारायण यादव

दमोह। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार, 29 जून को उन्होंने पथरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने तत्काल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से जानकारी ली। बताया गया कि संबंधित दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं और जिला मुख्यालय से मांग की गई है।

कलेक्टर ने तत्काल सीएमएचओ को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कई आवश्यक दवाएं समय पर जिला स्टोर से नहीं मंगाई गईं, जिसके कारण मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने अस्पताल परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र बंद मिलने पर नाराजगी जताई और ड्रग इस्पेक्टर को तत्काल निरीक्षण कर केंद्र को शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि वर्तमान संचालक केंद्र नहीं चला रहा है तो इसे किसी अन्य पात्र व्यक्ति को सौंपा जाए, ताकि आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें। डॉक्टर अपने निर्धारित कक्ष में बैठकर करें उच्चार निरीक्षण के दौरान यहाँ भी पाया गया कि डॉक्टर और डॉक्टर एक ही कक्ष में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे थे।

शिक्षा साधारण को असाधारण बना सकती है- कलेक्टर यादव

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने किया पथरिया स्थित, एम.एल.बी. स्कूल एवं मॉडल हाई स्कूल का निरीक्षण



स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज 29 जून सोमवार को पथरिया स्थित एम.एल.बी. स्कूल एवं मॉडल हाई स्कूल का निरीक्षण कर छात्र-छात्राओं से संवाद किया।

आज की जनधारा

दमोह। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज 29 जून सोमवार को पथरिया स्थित एम.एल.बी. स्कूल एवं मॉडल हाई स्कूल का निरीक्षण कर छात्र-छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व, अनुशासन और उज्वल भविष्य को लेकर विद्यार्थियों का

मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी कक्षाओं में टाइम-टेबल अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री

यादव ने छात्र-छात्राओं से कहा कि शिक्षा केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जीवन में आत्मसात कर व्यवहार में उतारना आवश्यक है। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी अमूल्य संपत्ति है जिसे कोई न तो चुरा सकता है और न ही बाँट सकता है। यही शिक्षा व्यक्ति को आत्मसम्मान दिलाती है और जीवन में सफलता का

मार्ग प्रशस्त करती है, उन्होंने कहा यदि वे आज कुछ वर्षों तक पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आने वाले कई दशक उनका जीवन सुखमय होगा तथा वे परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकेंगे। उन्होंने विद्यार्थी जताया कि पथरिया के विद्यार्थी अपने सपनों को अवश्य साकार करेंगे।

सड़क हादसे में 2 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों ने किया चक्काजाम, तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे आश्वासन देकर जाम खुलवाया



आज की जनधारा
दमोह। सोमवार सुबह सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौराहा पर हुए सड़क हादसे में 2 वर्षीय मासूम बच्ची जैसमीन पिता कैलाश वंशकार, निवासी मानस भवन दमोह की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल चौराहा स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतिका के परिजनों का कहना है कि ट्रक को शहर के भीतर नहीं आना चाहिए। परिजन बच्ची को

उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तहसीलदार रॉबिन जैन, कोतवाली टीआई मनीष कुमार, सब इंस्पेक्टर वंदना गौर, डॉक्टर एपी जैन, डॉक्टर अभिजीत सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने परिजनों को समझाशा दी और आश्वासन दिया कि नियम अनुसार कार्रवाई के साथ उचित मुआवजा दिलाने में हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को विधिक नोटिस; पिछ्ठी को लेकर दिए बयान पर जैन समाज ने मांगा 1 करोड़ का हजार्ना

आज की जनधारा

दमोह। दिगंबर जैन संत परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी के प्रवास के दौरान जैन मुनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 'पिछ्ठी' (मोर पंख से निर्मित धार्मिक उपकरण) पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जैन समाज के पदाधिकारियों और प्रतिष्ठित सदस्यों की ओर से मध्य प्रदेश के दमोह निवासी अधिवक्ता सिधई अभिषेक कुमार जैन ने मेनका गांधी को एक कानूनी (विधिक) नोटिस भेजा है। नोटिस में उनके बयान को पूरी तरह असत्य, भ्रामक और जैन धर्म की मूल भावनाओं के विपरीत बताते हुए 1 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया गया है।

क्या है पूरा मामला- नोटिस के अनुसार, हाल ही में मेनका गांधी दिल्ली के दिगंबर जैन लाल मंदिर पहुंची थीं, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि जैन

समाज द्वारा लाखों मोरों की हत्या करके उनके पंख प्राप्त किए जाते हैं और उससे पिछ्ठी बनाई जाती है। उन्होंने कथित तौर पर '15 लाख मोरों की हत्या' का समसमीक्षण आरोप भी लगाया था। नोटिस में जैन समाज के तर्क और आपत्तियां बिना प्रमाण के आरोपअधिवक्ता अभिषेक जैन ने नोटिस में कहा है कि मेनका गांधी ने बिना किसी वैधानिक अध्ययन, सरकारी अभिलेख या विश्वसनीय प्रमाण के इतना गंभीर आरोप लगाया है, जो केवल भ्रम फैलाने और जैन समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। प्राकृतिक रूप से मिलते हैं मोरपंख नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जैन मुनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिछ्ठी उन मोरपंखों से बनती है जो मोर द्वारा समय-समय पर प्राकृतिक रूप से स्वयं झाड़े (shed) जाते हैं। जैन धर्म में किसी भी जीव की हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। धार्मिक भावनाएं आहत इस बयान से देश-विदेश में रहने वाले करोड़ों जैन अनुयायियों और साधु-संतों की

गरिमा व सामाजिक सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। 15 दिनों का अल्टीमेटम और 1 करोड़ का हजार्ना- दमोह निवासी प्रेषक इंजी. ऋषभ कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन और दिलेश चौधरी की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में मेनका गांधी से निम्नलिखित मांगें की गई हैं: 1. नोटिस मिलने के *15 दिनों के भीतर* अपने बयान को पूरी तरह और बिना शर्त वापस लें। 2. राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर लिखित एवं वीडियो के माध्यम से 'सार्वजनिक माफी' मांगें। 3. भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने का लिखित आश्वासन दें। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो भारतीय न्याय संहिता (इटर), 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत सक्षम न्यायालय में 1 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति (मानहानि हजार्ना) के लिए दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

संगठन की मजबूती से ही समाज का सम्मान और विकास सुनिश्चित - श्रीमंत महाराज राज्यवर्द्धन सिंह

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सेवा भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सोमवार को पचोर स्थित महाराजी लक्ष्मी कुमारी बाग में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिला राजगढ़ द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह मूंडला के नेतृत्व में नवनिर्वाचित राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर का सम्मान किया गया। समारोह में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्रीमंत महाराज राज्यवर्द्धन सिंह नरसिंहगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्रीमंत महाराज राज्यवर्द्धन सिंह ने कहा कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब उसके लोग संगठित होकर समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। संगठन केवल पदों का ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, सेवा, संस्कार और परस्पर विश्वास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को शिक्षा, सामाजिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक पदाधिकारी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक



परंपराओं को संरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी को समाज से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, वह उसे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निभाएँ। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंचेंगी और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। इस दौरान श्रीमंत महाराज ने राजेंद्र सिंह तोमर को पुष्पमाला

पहनाकर सम्मानित किया तथा संगठन का नियुक्ति पत्र प्रदान कर नवीन दायित्व के सफल निर्वहन की मंगलकामनाएं दीं। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य महाराज कुंवर विश्व प्रताप सिंह नरसिंहगढ़, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिपेंद्र सिंह चौहान, कुष्णपाल सिंह (मेजर बना मूंडला), चंद्रपाल सिंह (लड्डू बना), मनराज सिंह परमार, गजेन्द्र सिंह केलवा सहित समाज के अनेक वरिष्ठजन, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने उमरी स्कूल में छात्रों को दिया कैरियर मार्गदर्शन

आज की जनधारा

दमोह। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सौरभ गंधर्व ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। एसडीएम ने छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के टिप्स दिए और आगामी भविष्य में बेहतर कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और कठिन परिश्रम के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



नरसिंहगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

आज की जनधारा

दमोह। जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंहगढ़-दमोह मार्ग पर रवि-सोम करीब 1 बजे देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार यादव को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक खडेरों गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी सहित पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया।



पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

वर्क ऑर्डर से पहले ठेकेदार ने शुरू किया सीवरेज चैंबरों का कार्य अखिर किसकी अनुमति से चल रहा काम

आज की जनधारा

बुधनी। नगर परिषद बुधनी द्वारा सीवरेज लाइन के चैंबरों की मरम्मत, उन्हें सड़क के लेवल तक लाने तथा कई स्थानों पर लोहे की जालियां लगाने के कार्य हेतु 12 जून को टेंडर जारी किया गया था, जिसका प्रकाशन 13 जून को एक समाचार पत्र में हुआ। लेकिन नगर में चर्चा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने एवं वर्क ऑर्डर जारी होने से पहले ही, यानी टेंडर जारी होने के दो-चार दिन बाद से ही संबंधित ठेकेदार ने बुधनी घाट के वाई क्रमांक 10 में कार्य शुरू कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों से यह जानकारी भी मिल रही है कि वाई क्रमांक 4 में भी संबंधित ठेकेदार द्वारा पहले से कार्य किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ था तो अखिर किसकी अनुमति से सार्वजनिक सड़क पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया? नगरवासियों का कहना है कि किसी भी शासकीय कार्य की शुरुआत विधिवत स्वीकृति एवं कायदेशर के बाद ही होना चाहिए। ऐसे में बिना



वर्क ऑर्डर काम शुरू होना कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। लोगों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर वस्तुस्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि जनता के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। नगर में यह चर्चा भी है कि बुधनी घाट स्थित झंडा चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस कार्य की जानकारी मिल गई थी। चर्चा के अनुसार उन्होंने मौके पर ही ठेकेदार को बुलाकर पूछा था, रयह

काम किसकी अनुमति से कर रहे हो? साथ ही यह भी कहा था कि यदि बिना अनुमति कार्य किया जा रहा है तो किसी भी कीमत पर इस कार्य का बिल भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद आज दिनांक तक संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य जारी रहने की बात स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर में यह भी चर्चा है कि अखिर यह ठेकेदार की दायिगिरी है या फिर नगर परिषद की किसी स्तर पर साठगांठ,

क्योंकि बिना वर्क ऑर्डर और कथित रूप से बिना अनुमति के कार्य प्रारंभ होने तथा आपत्ति के बाद भी काम जारी रहने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशांत जैन का हाल ही में मंडीदीप से बुधनी स्थानांतरण हुआ है।



गुरु सिख मॉल की बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ राहुल गांधी का नीट आंदोलन, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की

आज की जनधारा
बुरहानपुर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने बुरहानपुर में विरोध का अनूठा तरीका अपनाया। शहर के गुरु सिख मॉल की बड़ी स्क्रीन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विद्यार्थियों के हित में चलाए जा रहे आंदोलन के वीडियो प्रदर्शित किए गए। स्क्रीन पर राहुल गांधी कोटा में छात्रों से संबद्ध करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।



प्रदर्शित हुए आंदोलन के दृश्य- गुरु सिख मॉल में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राहुल गांधी के आंदोलन से जुड़े वीडियो और संदेश प्रदर्शित किए गए। इस दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामले ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

कांग्रेस नेताओं ने लगाए केंद्र सरकार पर आरोप- वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी

ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका आरोप था कि सरकार को छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हमीद काजी ने कहा कि राहुल गांधी का नीट परीक्षा से व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए



सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही से बच रही है और छात्रों की आवाज को अनदेखा कर रही है।

मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास- नगर निगम अध्यक्ष अनोता अमर यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक से देशभर के विद्यार्थियों और उनके परिवारों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कई दुखद घटनाक्रम सामने आए हैं, इसलिए राहुल गांधी विद्यार्थियों के हित में

आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गुरु सिख मॉल सहित विभिन्न माध्यमों से जन-जन तक पहुंचा रही है, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य की इस लड़ाई में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।

उज्जैन सहित प्रदेश में एमपी ट्रांसको के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशनों की सुरक्षा के लिए हाई-परफॉर्मंस एचडी सीसीटीवी कैमरे लगे

आज की जनधारा
उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने उज्जैन, ग्वालियर भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित राज्य के अपने एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशनों की सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाई-परफॉर्मंस एचडी सीसीटीवी कैमरों की स्थापना शुरू कर दी है। लगभग 8.15 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना विद्युत ग्रिड को चोरी, अनाधिकृत प्रवेश और संभावित नुकसान से सुरक्षित रखने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न से तोमर ने बताया कि ने आगे जानकारी दी कि परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 417 सबस्टेशनों पर कैमरे चरणबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की स्थापना से सबस्टेशनों की सुरक्षा एवं गश्त में मानव संसाधन के साथ तकनीक के उपयोग से सुरक्षा की दोहरी परत सुनिश्चित की जा सकेगी। उज्जैन के 9 सबस्टेशन उज्जैन जिले के 400 केवी सबस्टेशन ताजपुर उज्जैन, 220 केवी सबस्टेशन उज्जैन और 132 केवी के 7 सबस्टेशनों ज्योति नगर उज्जैन, रातडिया, भेरुगढ़, घोंसला, तराना, माकड़ौन & विक्रम उद्योगपुरी पर सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं।



टैकनोलॉजी आधारित सुरक्षा कवच - ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह केवल चोरों के जीवन को खतरा होता है, बल्कि ट्रांसफॉर्मर फेल होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को तीन से चार माह तक बिजली आपूर्ति से वंचित होना पड़ सकता है। कॉपर स्ट्रिप चोरी के कारण ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होता है, तो कंपनी को आर्थिक क्षति के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था दो से तीन माह तक प्रभावित हो सकती है। ट्रांसफॉर्मर प्रायः ऑर्डर पर निर्मित होते हैं, इसलिए उन्हें बदलने में कई महीने लग जाते हैं। स्थापित एचडी कैमरे सबस्टेशनों को 360 डिग्री कवरेज प्रदान कर रहे हैं तथा इनमें नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और हाई-रिजॉल्यूशन रिकॉर्डिंग जैसे आधुनिक तकनीकें भी उपलब्ध हैं। इससे रात के समय या दूरस्थ क्षेत्रों में भी संदिग्ध गतिविधियों को पहचान आसानी से की जा सकेगी। लाइव फीड अधिकारियों के मोबाइल पर-इन कैमरों का लाइव फीड संबंधित सबस्टेशन प्रभारियों को उनके मोबाइल उपकरणों पर उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑफिकल फाइबर नेटवर्क के एकीकरण के माध्यम से जबलपुर स्थित शक्तिभवन मुख्यालय के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से प्रदेश के सभी 417 सबस्टेशनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग का कार्य प्रगति पर है।

एचडी सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से सबस्टेशनों की सुरक्षा एवं गश्त में मानव संसाधन के साथ तकनीक के उपयोग से सुरक्षा की दोहरी परत सुनिश्चित की जा सकेगी। उज्जैन के 9 सबस्टेशन उज्जैन जिले के 400 केवी सबस्टेशन ताजपुर उज्जैन, 220 केवी सबस्टेशन उज्जैन और 132 केवी के 7 सबस्टेशनों ज्योति नगर उज्जैन, रातडिया, भेरुगढ़, घोंसला, तराना, माकड़ौन & विक्रम उद्योगपुरी पर सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं।

टैकनोलॉजी आधारित सुरक्षा कवच - ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह

हिंदू साम्राज्य दिवस पर निकली भव्य शोभायात्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज को किया नमन

आज की जनधारा

सोहागपुर। सकल हिंदू समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय काली मंदिर परिसर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभागाध्यक्ष प्रमुख मनीष सहायिया ने कहा कि भारत प्राचीन ऋषियों, महत्पुरुषों, ज्ञानियों और विज्ञानियों की पावन भूमि है। यह देश कभी विश्व गुरु और सोने की खिड़िया के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि जब-जब इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ा है, तब-तब ईश्वरीय शक्तियों ने अवतार लेकर धर्म और संस्कृति की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग से लेकर कलियुग तक धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहा है। इसी क्रम में मुगलकाल में जब हिंदू



समाज पर अत्याचार हो रहे थे, तब महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में माता जीजाबाई ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से मुगलों को चुनौती देकर स्वाभिमान, संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और उन्हें

रक्षत्रपतिर की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर को आज पूरा भारतवर्ष हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हिंदू समाज के लिए प्रेरणा, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। मंचीय कार्यक्रम में धर्म जागरण के जिला सह संयोजक गृहस्थ संत भूपे गिरी महाराज तथा समाजसेवी कृष्ण कुमार पालीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिवकुमार

पटेल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रभारी विशाल गोलांनी ने व्यक्त किया। सभा के पश्चात काली मंदिर परिसर से छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो शासकीय कन्या शाला, बिहारी चौक, कमनिया गेट और श्रीराम चौराहे से होते हुए पुनः काली मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में रामगंज वार्ड के अखाड़े के युवाओं ने आकर्षक एवं साहसिक करतब प्रस्तुत किए। इस दौरान

आतिशबाजी ने उत्सव के माहौल को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में समाजसेवी कन्लाल अग्रवाल, कृष्ण पालीवाल, प्रदेश मंत्री राजो मालवीय, जीवन दुबे, जिला कार्यालय नरेंद्र मिश्रा, राघवेंद्र पटेल, कार्यक्रम संयोजक रितेंद्र राजपूत, सतपाल सिंह राजपूत, मंगल सिंह रघुवंशी, अमित बिल्लोरे, राकेश चौरसिया, मोहन कहार, अखिलेश मालवीय, प्रहलाद गढ़वाल, उदल रघुवंशी, भाव भवसार, मुणाल घरामी, राकेश गोस्वामी, हिमांशु गुर्जर, बाबू मेहरा, लकी तिवारी, सोरभ हलदर, दिव्यांश मेहरा, निलेश शर्मा, मयंक मंडल, अर्जुन कुशवाहा, मोहित कहार सहित बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी नागरिक उपस्थित रहे। शोभायात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप धारण कर ऋतिक मालवी विशेष आकर्षक का केंद्र रहे।

उज्जैन ऑपरेशन Safe Click 2.0 के अंतर्गत थाना चिंतामण पुलिस द्वारा शासकीय विद्यालय, जवासा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज की जनधारा
उज्जैन। पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार संचालित ऑपरेशन Safe Click 2.0 के अंतर्गत थाना चिंतामण पुलिस द्वारा 29.06.2026 को शासकीय विद्यालय, जवासा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान थाना चिंतामण पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को वर्तमान समय में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों, जैसे फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, सोशल मीडिया फ्राड, ऑनलाइन गेमिंग एवं निवेश संबंधी धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग तथा



डिजिटल माध्यमों से होने वाले अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को समझाइश दी गई कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम, पासवर्ड अथवा अन्य व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।



विद्यार्थियों को साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया का जिम्मेदार/दुरुपयोगी उपयोग करने,

अफवाहों से दूर रहने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सतर्कता बरतने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सख्त छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को साइबर सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहने, सुरक्षित डिजिटल आस्तियों को अपनाने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। उज्जैन पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।

उज्जैन थाना यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई में सहयोग नहीं करने वाले ऑटो चालक पर सख्त कार्रवाई

आज की जनधारा
उज्जैन। पुलिस द्वारा शहर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा एक ऐसे ऑटो चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जिसने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ चेकिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ऑटो चालक शदाव पिता अकरम पठान, उम्र 25 वर्ष, निवासी सम्राट नगर, आगर रोड, उज्जैन द्वारा संचालित ऑटो वाहन के आवश्यक दस्तावेज, जिनमें वाहन से संबंधित वैधानिक कागजात



सम्मिलित हैं, निर्धारित अवधि से समाप्त हो चुके थे। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहने पर चालक द्वारा

पुलिस कार्रवाई में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया, जिसके चलते नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की

गई। यातायात पुलिस द्वारा तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो वाहन को जप्त किया गया तथा प्रचलित मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयीन चालान प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन पुलिस आम नागरिकों, विशेषकर यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे ऑटो चालक जो बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालित करते हैं अथवा चेकिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई में सहयोग नहीं करते, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेन हादसे में पैर गंवा चुके युवक ने जिला अस्पताल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा, ओटी की खिड़की पर चढ़ा

आज की जनधारा
बुरहानपुर। जिला अस्पताल में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेन हादसे में अपना एक पैर गंवा चुके एक युवक ने पिता से कहासुनी के बाद अस्पताल की गैलरी से पाइप के सहारे ऑपरेशन थिएटर (ओटी) की खिड़की तक पहुंचकर बैठ गया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन, पुलिस और नगर निगम की फायर टीम मौके पर पहुंची। करीब डेढ़ घंटे की मशरकत, समझाइश और रेस्क्यू अभियान के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। ट्रेन हादसे के बाद जिला अस्पताल में चल रहा था उपचार- जानकारी के अनुषंग, तुकईथड़ क्षेत्र के बिजौरी गांव निवासी युवक को दो दिन पहले ट्रेन हादसे में दाहिना पैर कट गया था। हादसे के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। रविवार रात



करीब नौ बजे उपचार के दौरान पिता से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद युवक मानसिक रूप से भी काफी परेशान था। गैलरी से पाइप के सहारे ओटी की खिड़की पर पहुंचा-विवाद के कुछ देर बाद युवक वाई

की गैलरी से बाहर निकला और पाइप के सहारे चढ़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की खिड़की पर जाकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। इयूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने तत्काल स्थिति सज्जन डॉ. वर्पण टोके और अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस, फायर टीम और अस्पताल प्रबंधन ने चलाया रेस्क्यू अभियान- सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की फायर टीम जिला अस्पताल पहुंची। फायर वाहन की सीढ़ी की मदद से युवक तक पहुंचने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक युवक को समझाया और भरोसा दिलाया कि उसकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आश्चर्यकर करीब डेढ़ घंटे की मशरकत के बाद कर्मचारी उसे सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहे।

उज्जैन थाना महिदपुर क्षेत्र का निगरानी बढमाश व चार माह से अवैध वसूली के प्रकरण में फरार आरोपी गिरफ्तार

आज की जनधारा

उज्जैन। जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी व अवैध गतिविधियों में सलियत लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) करणदीप सिंह (भापुसे), एसडीओपी जेडेन लिंगजेरा (भापुसे) के मार्गदर्शन में जिसके तारतम्य में थाना महिदपुर टीम द्वारा करीब 04 माह से फरार आरोपी निजामुद्दीन को 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-घटना दिनांक 23.02.2026 को आरोपी निजाम उर्फ निजामुद्दीन पिता मोईउद्दीन निवासी फकीर मोहल्ला महिदपुर व उसके 03 अन्य साथियों द्वारा स्वयं को महिदपुर का किंग बताकर फरियादी को बोले यदि तुझे महिदपुर में रहना है तो हम लोगों को हमारे घर पर लगे सीटीटीवी कैमरों के मॉडैमस का खर्च तुझे देना पड़ेगा व अभी 10,000 रु. दे, पैसे देने से मना करने पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर फरियादी के



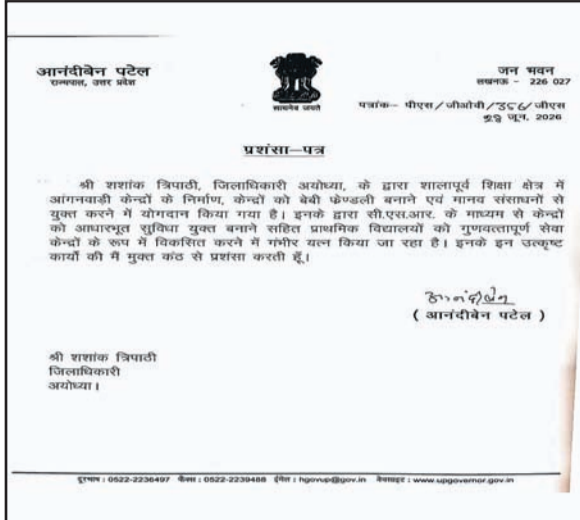
साथ लात-चूंसो व लोहे के पाईप से मारपीट की

दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर में 36/2026 धारा 119(1), 333,115(2),

296बी, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. का उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध कायम कर अनुसंधान में लिया गया। दौरान विवेचना करीब 04 माह से फरार आरोपी निजाम उर्फ निजामुद्दीन पिता मोईउद्दीन निवासी फकीर मोहल्ला महिदपुर को करबा भ्रमण के दौरान दिनांक 28.06.2026 को 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ जहरीली शराब के साथ के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी का आपराधिक रिकार्ड- आरोपी ने निजाम उर्फ निजामुद्दीन के विरुद्ध वर्ष 2012 से 2026 के बीच कुल 21 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, जानलेवा हमला, दंगा करने, जुआ सट्टा, अवैध वसूली, आमर्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं।

सराहनीय भूमिका - उक्त प्रसंशनीय कार्य में निरीक्षक अशोक पाटीदार, उति. सुखसेन अरियाम, सजिन. राधेलाल निनामा, प्र.आर. नारायणसिंह, आर. आदिराम, आर. राघव, आर. लेखराज, आर. पंकेश पाटीदार, आर. संजयसिंह, म.आर. दुर्गा, आर. चालक नारायण की सराहनीय भूमिका रही है।

यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अयोध्या के DM शशांक त्रिपाठी IAS की सराहना की, भेजा प्रशंसा-पत्र



आज की जनधारा
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा-पत्र भेजा है। यह सम्मान शालापूर्व शिक्षा के क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, उन्हें बेबी फ्रेंडली बनाने तथा मानव संसाधनों से सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए दिया गया है। 28 जून 2026 को जारी प्रशंसा-पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा सीएसआर के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को

आधारभूत सुविधाओं से युक्त बनाने और प्राथमिक विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण सेवा के रूप में विकसित करने की दिशा में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने अपने संदेश में लिखा कि शशांक त्रिपाठी द्वारा किए जा रहे इन उत्कृष्ट कार्यों की वह मुक्त कंठ से प्रशंसा करती हैं और उनके प्रयास अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उल्लेखनीय है कि शशांक त्रिपाठी वर्तमान में अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और हाल ही में उनकी इस महत्वपूर्ण जनपद में नियुक्ति हुई है।

योगी सरकार 1.04 करोड़ से संवारेगी गोमती नदी का उद्गम स्थल पर्यटन विभाग की पहल, पीलीभीत जिले में स्थित मां गोमती उद्गम स्थल पर विकसित होगी पर्यटन सुविधाएं



आज की जनधारा
लखनऊ/पीलीभीत,। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्य धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के व्यापक विकास के बाद अब प्रदेश सरकार ने जीवनदायिनी मां गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्वस्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 1.04 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम चरण में 78 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा। करोड़ों लोगों

के जीवन और आजीविका का आधार उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मानव सभ्यता का विकास संदेव नदियों के तटों पर हुआ है। प्रदेश की जीवनदायिनी एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटांडा ग्राम के समीप गोमत ताल (पूर्व नाम फुलहर झील) से होता है। सनातन परंपरा में अत्यंत प्रतिष्ठित गोमती नदी प्रदेश के विशाल भूभाग को सिंचित करते हुए करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा गोमती उद्गम स्थल को एक प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन आकर्षण के लिए होंगे कई काम परियोजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। इसके तहत लगभग 48.69 लाख रुपये की लागत से बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा, जबकि



13.44 लाख रुपये से आधुनिक शौचालय ब्लॉक और 9.45 लाख रुपये से शोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंटरलॉकिंग मार्ग, आकर्षक उद्यान एवं सौंदर्यीकरण, सोलर आधारित सुविधाओं, अन्य यात्री सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) को मिली है।

पत्रकारपुरम चौराहे के निकट मारपीट एवं फायरिंग की घटना



आज की जनधारा
लखनऊ। गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत पत्रकारपुरम चौराहे के निकट मनीष इंटींग व्हाईट पर दो पक्षों के बीच मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक कर्मचारी गोली लगने से घायल हुआ। घायल का उपचार कराया गया तथा चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य एवं खतरों से बाहर है। प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना गोमतीनगर पर दो अभियोग पंजीकृत किये गए हैं। जिसमें में दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल अन्य नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है तथा घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का गहन परीक्षण किया जा रहा है।

न्यूज. बीफ

प्रदेश में 29 जून से सक्रिय होगा मानसून

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में गरज-चमक का अलर्ट हुआ जा रही। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 30 जून से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी। जुलाई के पहले साहज में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के लिए परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और छिप्टेनुत बारिश के आसार हैं। वहीं 30 जून से प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल दो दिन यूपी के सोनभद्र, मिजापुर और चंदौली जैसे दक्षिणी जिलों में बारिश भरी गर्मी बरकरार रहने वाली है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के 66 जिलों में गरज-चमक और नवपात की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा तराई क्षेत्र के कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन जिलों में है मेघगर्जन व वज्रपात की चेतावनी बांदा, चित्रकूट, कोशीबां, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतागढ़, सोनभद्र, मिजापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरिया, बिजनौर, अमरौहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

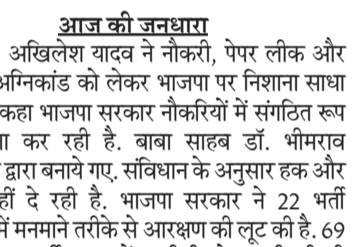
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता से पूछा- इतनी जल्दबाजी क्यों

आज की जनधारा
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले की सीबीआई के नेतृत्व में जांच कराने की याचिका पर न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आखिर इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है। अदालत ने कहा कि अवकाश समाप्त होने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति शील नाग की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में हुए गबन की जांच के लिए सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरोप बेहद

गंभीर हैं और राज्य सरकार जिस तरह से मामले को संभाल रही है, उससे संदेह पैदा हो रहा है। इस पर न्यायमूर्ति सुंदरश ने पूछा, हड़स मामले में इतनी जल्दबाजी क्या है? अदालत ने अंततः कहा कि अदालत दोबारा खुलने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला ?
सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने 7 जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी की थी। इसके बाद 8 जून सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। 9 जून को भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मामले को उड़क और एऊ से जांच की मांग की। 9 जून को राम मंदिर

निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। चढ़ावे की राशि, गिनती और लेखा-जोखा पर चर्चा की। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांगी ली। दूसरी तरफ, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोप खारिज किए। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया।
राम मंदिर दान चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर.
सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी।

नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन नौकरी, पेपर लीक और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भाजपा पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना



आज की जनधारा
लखनऊ। अखिलेश यादव ने नौकरी, पेपर लीक और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार नौकरियों में संगठित रूप से घोटाला कर रही है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये गए संविधान के अनुसार हक और सम्मान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं में मनमाने तरीके से आरक्षण की लूट की है। 69 हजार शिक्षक भर्ती 2019 में आवेसी को 27 फीसदी की जगह 3.8 फीसदी, एससी को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी की जगह शून्य आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए ऑडिट अंक-1 पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट में 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का आंकड़ा जारी किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के जिले में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में हो रहे भ्रष्टाचार और गोरखधंधा की रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन भाजपा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया। झूठा वादा किया। भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक रहे हैं। महाराष्ट्र में कल भी टीईटी का पेपर लीक हो चुका है। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल 2018, ग्राम विकास

पंचायत भर्ती 2018, नलकूप चालक भर्ती 2018, यूपी टीईटी परीक्षा 2021, दो बार यूपीपीएससी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020, 2022, 2025, सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ, यूजीसी नेट 2024, एसएसपीसी जीडी 2026, लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा 6 साल तक लटकी रही, परिणाम हाईकोर्ट से रद्द हुआ। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको सरकारी संस्थाओं से परेशान किया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। भाजपा ने पीडीए समाज को धोखा दिया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को धोखा दे रही है। भाजपा के शब्दकोष में न धर्म बचा है और न शर्म बची है। इनकी प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। भाजपा चतुराई और चालबाजी करती है।

CM योगी की पाती: 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का आह्वान

आज की जनधारा
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पाती में स्कूली बच्चों और गुरुजनों के लिए संदेश दिया है। योगी ने लिखा कि जुलाई नवीन माह का आरंभ ही नहीं, सौभाग्य लाक्या बच्चा के सपना का विद्यालय तक पहुंचाने के नए संकल्प का समय है। उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कक्षा से 12वीं तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना और नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश अभियान को गति देना है। सीएम ने आगे लिखा हज्जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति की जब भी चर्चा होती है, तो मांस पटल पर केवल विद्या का नाम आता है। ज्ञान के पंख ही बच्चों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। विद्यालय वह पवित्र स्थान है, जहां से छात्र-छात्राओं के ज्ञान, संस्कार और जीवन-धर्म के साथ ही चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा आरंभ होती है। यही सनातन परंपरा भी है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर नैतिक, उपनिषद, शास्त्र, विज्ञान, शिल्प, धनुर्वेद, कृषि, नीति और जीवन-मूल्यों के सांचे में ढलते थे। आज के विद्यालय उसी गुरुकुल परंपरा के आधुनिक



संस्था आधार विद्यालय ही है। हमारी सरकार ने इसी मंशा से प्रोजेक्ट अलंकार शुरू किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा का प्रकाश पूरे प्रदेश को आलोकित करे, इसलिए हमारी सरकार ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और हामिशन निपुण जैसे अभियान चला रही है, ताकि हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, स्वस्थ मरिक्तक के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूलों में विविधतापूर्ण गर्म पका-पकामा रुचिकर भोजन की व्यवस्था की गई है, सीएम ने आगे लिखा कि ह्यप्रिय गुरुजनों, कुछ बातें मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। आप सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल को दैनिक रूटीन का हिस्सा मात्र न समझें, बल्कि विद्यालय जाने में रुचि दिखाएं, खेल-कूद आदि गतिविधियां इसके लिए बेहतर माध्यम हो सकती हैं। अभिभावक अपने बच्चों का मूल्यांकन उनके नंबरों से नहीं, बल्कि उनके होसले और लगन से करें। स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति आपको ही सुनिश्चित करनी होगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न

संगठनात्मक समीक्षा एवं शिक्षक समस्याओं के समाधान पर हुआ मंथन



आज की जनधारा
लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश संचालन समिति एवं साधारण सभा की बैठक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अलीगंज, लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संचालन प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने किया। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांचन, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ।



बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, सदस्यता अभियान, गुरुवंदन कार्यक्रम, कर्तव्य बोध दिवस, हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ अभियान सहित आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पीडीए बैठक में समाजवादी मजदूर सभा ने भरी हुंकार

धार्मिक भावनाओं को टेस पहुंचाने के आरोप में नाजिया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज
लखनऊ। थाना मदेयगंज में नाजिया इलाही खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में नफरत फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिव नगर, खदरा निवासी जुनेद अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 19 जून 2026 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक रील में नाजिया इलाही खान ने मुस्लिम समुदाय और पैगंबर के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह बयान मोहरम की तैयारियों के दौरान समाज में सौहार्द बिगड़ने के उद्देश्य से दिया गया है। पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

विधानसभा चुनाव के लिए बनाई योजना

आज की जनधारा
लखनऊ। गांव गैसपुर सिकन्दराबाद विधानसभा 64 जिला बुलन्दशहर समाजवादी मजदूर सभा द्वारा पीडीए बैठक का आयोजन किया गया बैठक में बोलते हुए चौधरी चंद्रपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जनता जनार्दन की पुकार है किसान मजदूरों को अखिलेश यादव की सरकार में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई थीं। भाजपा सरकार गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है धर्म आस्था का जो खेल भाजपा ने खेला अब उसका पर्दा पास हो गया है भगवान राम के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी चढ़ावे की हुई है ट्रस्ट में जितने भाजपा के नेता राम मंदिर ट्रस्ट में थे उन्होंने ही भगवान राम के चढ़ावे की चोरी कि है जो गरीब मजदूर मंदिर में देखरेख करते हैं सफाई व्यवस्था में रहते हैं उन गरीब मजदूरों को फसाया जा रहा है हम मांग करते हैं मंदिर की देख रेख स्वामी संत समाज ही कर सकता है अयोध्या श्री राम मंदिर साधू सन्यासियों को सोंपा जाय।

हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था करा रही सरकार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले

आज की जनधारा
लखनऊ,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हज्जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना। उनका प्रार्थना पत्र लिया और संबंधित अधिकारियों को देकर निर्देशित किया कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान तय समयसीमा के भीतर हो। इसके उपरांत पीडित पक्ष से बात कर उनकी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाए। मुख्यमंत्री ने पीडितों को आश्वासन करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम हर मामले का उचित निस्तारण कराएंगे। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी बरेली से एक महिला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कैसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और आर्थिक सहायता की मांग की। सीएम ने उनसे हॉस्पिटल का एस्टिमेट मांगा, जिसे वह तत्काल उपलब्ध न करा सकीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हॉस्पिटल



से एस्टिमेट मंगवा लीजिए। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने मरीज को एडमिट कराने और उनके समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया। राजस्व मामले पर बोले सीएम- वादकारियों को समय से न्याय दिलाया सरकार की मंशा हज्जनता दर्शनहमें राजस्व संबंधी मामले भी आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया। कहा कि इस पर जल्द निर्णय होने से वादकारियों को समय से राहत मिलती है। राजस्व से जुड़े अधिकारी समय से न्यायालय में बैठें। इस संबंध में निर्णय भी जल्द दें, क्योंकि ऐसा न होने से गरीब वादकारी अधिक प्रभावित होते हैं। वादकारियों को न्याय दिलाया सरकार की मंशा है। इसके अनुरूप राजस्व से जुड़े अधिकारी जरूरतमंदों को न्याय दिलाएंगे।

जिले के 13 थाने हुए आइएसओ अवार्ड, आईजी की मौजूदगी में एनकेजे थाने में हुआ सर्टिफिकेट का वितरण

थानों के निरीक्षण किया पुलिस महानिरीक्षक ने

आज की जनधारा कटनी। जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (एडीजी) प्रमोद कुमार वर्मा एवं आइसी भोपाल टीम के अधिकारियों की मौजूदगी में आज कटनी जिले के 13 पुलिस थानों एवं तीन पुलिस कार्यालय को आइएसओ सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। एनकेजे थाने में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में जिले के सभी 13 थानों के थाना प्रभारियों को आइएसओ सर्टिफिकेट का वितरण किया। इस अवसर पर आइसी प्रमोद कुमार वर्मा ने आइएसओ अवार्ड एनकेजे थाने का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके उपरांत एनकेजे थाना प्रभाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आइसी प्रमोद कुमार वर्मा की उपस्थिति रही। मंच पर अन्य अतिथियों के रूप में कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा, वन मण्डल अधिकारी गवित गंगवार, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मोर्य, एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, नगर पुलिस



अधीक्षक नेहा पचवीसया, डीएसपी अजाक शिवा पाठक, एसडीओपी स्लीमनाबाद आकांक्षा चतुर्वेदी, एसडीओपी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धारवे, डीएसपी रत्नेश मिश्रा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने आइसी प्रमोद कुमार वर्मा का पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। मंचासीन अन्य अतिथियों का भी अभिनन्दन किया गया। इसके उपरांत आइएसओ

कंसल्टेंट योगेंद्र दिवेदी ने आइएसओ सर्टिफिकेट के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आज कटनी जिले के 13 थाने और तीन पुलिस कार्यालयों को आइएसओ अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद एक डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण किया गया और पत्रिका का विमोचन किया गया।

जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने जबलपुर से रवाना होने के बाद स्लीमनाबाद थाने, यातायात, कोतवाली, कुठला एवं एनकेजे थाने का निरीक्षण किया। एवं माधव नगर एवं एनकेजी थाने का निरीक्षण करते हुए अवलोकन किया। ये थाने हुए आइएसओ अवार्ड- आइएसओ सर्टिफिकेट के लिए जिन थानों को तैयार किया गया है, उसमें कोतवाली, कुठल, माधवनगर, एनकेजे, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद, उमरियापान, दीमरखंडा, बड़वारा, विजयराघवगढ़, बरही एवं यातायात थाना शामिल है, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एसडीओपी स्लीमनाबाद एसडीओपी विजयराघवगढ़ कार्यालय भी इसमें शामिल है।

आज राजगढ़ को मिलेगी विकास की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे 352 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

जल गंगा संवर्धन अभियान में उज्जैन जिला प्रदेश के टॉप-5 में शामिल

आज की जनधारा पचोर/राजगढ़। राजगढ़ जिले के लिए मंगलवार का दिन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिले के सारंगपुर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध भैसावामाता धाम पहुंचकर राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे जिले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 352 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर विकास की नई सौगात देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम धार्मिक और विकाससात्मक गतिविधियों का संगम होगा। वे सर्वप्रथम भैसावामाता मंदिर में पहुंचकर दर्शन एवं पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद दूध तलेया परिसर में आयोजित जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गंगा पूजन, गौ-पूजन तथा पौधरोपण करेंगे। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा,



कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल तथा सांसद रोडमल नागर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। राजगढ़ जिले की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। समारोह में जिले पर आधारित पर्यटन फिल्म, कॉफी टेबल बुक तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में संपन्न हुए विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने वाली विशेष पुस्तक का विमोचन भी होगा। मुख्यमंत्री विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समूहों और संस्थाओं को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बैठक व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिले भर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में यह समारोह विकास, जल संरक्षण और जनकल्याण का महत्वपूर्ण आयोजन बनने जा रहा है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोकने मैदानी स्तर पर कार्य करें

आज की जनधारा शहडोल। शहडोल एवं रीवा संभाग के क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. जी.एस. परिहार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शहडोल के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए मैदानी स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा करें जिससे मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य ने स्वास्थ्य विभाग में लॉन्च सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा



करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लॉन्च शिकायतों का निराकरण समय सीमा में प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें कोई भी प्रकरण अनअटेंड न रहे। उन्होंने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त कार्यक्रम का उन्मूलन 2026 तक निर्धारित किया गया है इसके लिए सशक्त कार्य

सांची विधायक डॉ चौधरी ने बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा, पल्स पोलिंग अभियान की शुरुआत

आज की जनधारा रायसेन। सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा आज जिला अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलिया अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय, सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉ अनिल ओड सहित अन्य अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित रहे। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को जिले में बनाए गए 740 बूथों पर रविवार को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईट भट्टों तथा



चलित आबादी बस्ती में पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के तहत 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर भ्रमण कर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

अवैध रेत से भरा हाईवा पुलिस ने पकड़ा

आज की जनधारा शहडोल। जिले की ब्यौहारी पुलिस द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ब्यौहारी पुलिस ने अवैध रेत से भरा एक हाईवा पकड़ा है। ब्यौहारी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कन्हारी स्थित समथिन नदी के पास झाड़ियों के बीच एक हाईवा ट्रक में अवैध रूप से रेत लोड की जा रही है तथा हाईवा वाहन तकनीकी खराबी के कारण मौके पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल ब्यौहारी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां हाईवा ट्रक क्रमांक एएमपी 18 जेड सी 4010 में रेत लोड पाई गई। मौके पर उपस्थित चालक राम सजीवन यादव निवासी ग्राम अमलई, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी से पूछताछ की गई तो चालक वाहन में लोड रेत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर उपलब्ध तथ्यों एवं वैध



दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने हाईवा में लोड लगभग 50 हजार रुपये मूल्य की अवैध रेत सहित हाईवा को विधिवत जप्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि उक्त मामले में चालक राम सजीवन यादव, वाहन स्वामी दीमानु मिश्रा उर्फ छोटू तथा रेत ठाहा संचालक अतुल सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), खान एवं खनिज

किसानों को वितरित किया उड़द बीज, खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों की दी जानकारी

आज की जनधारा अमित सोनी। विदिशा। खरीफ वर्ष 2026 की बुवाई को ध्यानगत रखते हुए कृषि विभाग विदिशा द्वारा किसानों को उन्नत गुणवत्ता का उड़द बीज उपलब्ध करने के साथ-साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसंचालक सचिन जैन ने बताया है कि ग्राम पीपलखंडा, भूतपारा सी, पोआनाला, कबूला एवं बागरी के किसानों को गुणवत्तायुक्त उड़द बीज का वितरण आज किया गया। बीज वितरण कार्यक्रम संबंधित कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सरपंचों एवं जनपद सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को समय पर उन्नत बीज उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है, जिससे खरीफ



फसलों की बुवाई समय पर हो सके और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। बीज वितरण का मुख्य उद्देश्य उड़द की उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस अवसर पर कृषि अधिकारियों ने किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। किसानों को बुवाई से पूर्व बीजोपचार करने, अनुशासित किस्मों का चयन करने, समय

पर बुवाई करने तथा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी गई। साथ ही खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन (आईपीएम), खरपतवार नियंत्रण, मौसम आधारित कृषि सलाह का पालन तथा वैज्ञानिक खेती की आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लाभों से भी किसानों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन लागत कम होती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। कृषि विभाग ने किसानों से शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने तथा तकनीकी मार्गदर्शन के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारियों से नियमित संपर्क बनाए रखने की अपील की।

गहरे गड्ढे से बरामद मानव कंकाल, महिला के कपड़े और खोपड़ी मिलने से बढ़ा रहस्य

आज की जनधारा पचोर। क्षेत्र के सुल्तानिया गांव के समीप स्थित पहाड़ी क्षेत्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक गड्ढे से मानव कंकाल मिलने की सूचना सामने आई। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पड़ताल में गड्ढा गहरा होने के कारण पुलिस ने जेसीवी मशीन की सहायता से खुदाई कराई। खुदाई के दौरान मानव कंकाल बाहर निकला गया। घटनास्थल से महिला के कपड़े तथा एक खोपड़ी भी बरामद होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मौके का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और बरामद सामग्री को जांच



के लिए सुरक्षित कर लिया। फिलहाल कंकाल की पहचान नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अवशेष कितने पुराने हैं और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। इन सभी पहलुओं का खुलासा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस मामले की हर संभावित दिशा में जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, ताकि कंकाल की पहचान स्थापित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस रहस्यमयी बरामदगी ने पूरे क्षेत्र में चर्चा और उत्सुकता का माहौल बना दिया है।

प्रदेश स्तर पर हुई बिंदुवार समीक्षा, विधायक डॉ. चौधरी ने जनहित से जुड़े विषयों पर की गंभीरतापूर्वक चर्चा

आज की जनधारा रायसेन। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के कक्ष क्रमांक-07 में आयोजित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में पूर्व मंत्री सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, विधायक जयसिंह मरावी, राजेन्द्र मश्रम, पन्नालाल शांभू एवं कालुसिंह ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विस्तृत बिंदुवार समीक्षा की गई। आस्था प्रस्तुत करने हेतु विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बागरा, अनुसूचित जाति विभाग आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विभाग आयुक्त, अपर आयुक्त एवं उप सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा



समिति के समक्ष विभिन्न प्रश्नों के उत्तर एवं आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत जल संसाधन विभाग की भी व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजीरा, अपर सचिव रविन्द्र चौधरी, अधीक्षण यंत्री एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और विभागीय कार्यों की प्रगति एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक में तीनों विभागों के कार्यों

जनजातीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और अस्मिता का विराट राष्ट्रीय प्रतीक बनकर सामने आया देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति समागम

आज की जनधारा कटनी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 24 मई को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति समागम-2026 के सफल आयोजन के बाद जनजाति सुरक्षा मंच महाकौशल प्रांत के संयोजक महेश कुमार कोल व सहसंयोजक अमोल सिंह मार्को का आज अल्प प्रवास पर कटनी आगमन हुआ। कटनी प्रवास के दौरान सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाऊस में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंत्र के दोनों पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 24 मई को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति समागम-2026 जनजातीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और अस्मिता का



विराट राष्ट्रीय प्रतीक बनकर सामने आया है। देशभर के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों से आए लाखों जनजातीय बंधु-भगिनी पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, लोकनृत्य, वाद्ययंत्रों और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ इस समागम में सम्मिलित हुए। जनजाति समागम-2026 को लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर समाज की आस्था, संस्कृति, प्रकृति-पूजा, जल-जंगल-जमीन और जीवन-तद्घति को भारत की सांस्कृतिक आत्मा से जोड़ा हुआ बताते हुए कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय समाज के महाकुंभ के रूप में स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने बिना लिखित नियमों के अनेकता में एकता और एकता में अनेकता के मंत्र को जीवन में साकार किया है। पत्रकारवार्ता में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वनवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष बाबू भाई सोधिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार आनंद, जिला रक्षा प्रमुख नरेन्द्र सिंह, जिला सहा सचिव सुनील रावत, प्रचार प्रसार प्रमुख कमल मोहनानी व मिथिलेश यादव उपस्थित रहे। उन्होंने जनजातीय

खबर का असर— बलियरी में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी से रास्ते खुदवाकर रोका आवागमन

आज की जनधारा
सिंगरौली । सिंगरौली जिले बैदुन थाना क्षेत्र के ग्राम बलियरी में लंबे समय से कथित अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को लेकर ग्रामीणों द्वारा उठाई जा रही शिकायतों और समाचार प्रकाशन का असर आखिरकार देखने को मिला। लगातार विरोध, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत और मामले के मीडिया में आने के बाद खनिज विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नदी तक जाने वाले कच्चे रास्तों को जेसीबी से खुदवाकर अवरुद्ध कर दिया, जिससे अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टरों की आवाजाही पर तत्काल रोक लग गई। ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्र की नदियों से लगातार अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था और रातभर बड़ी संख्या में रेत से भरे ट्रैक्टर गांव से गुजरते थे। ट्रैक्टरों के तेज शोर और रस्तर से लोगों को नींद प्रभावित हो रही थी, वहीं कई स्थानों पर नालियों और मकानों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आई थीं। ग्रामीणों का कहना था कि इससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने कई बार संबंधित विभागों और प्रशासन से



शिकायत की, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने स्वयं रेत से लदे ट्रैक्टरों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया था कि अवैध रेत उत्खनन से एक ओर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है। हालांकि, इन आरोपों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खनिज विभाग और

पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नदी तक पहुंचने वाले कच्चे मार्गों पर जेसीबी से गहरे गड्ढे खुदवाकर रास्ते बंद कर दिए, ताकि अवैध परिवहन करने वाले वाहन नदी तक न पहुंच सकें। इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध रेत उत्खनन अथवा परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।



पहली ही बारिश में डूबा कॉलेज रोड, जलभराव से घंटों जाम में फंसे लोग; नगर निगम की तैयारियों की खुली पोल

आज की जनधारा
सिंगरौली । सिंगरौली जिले में सोमवार को मानसून ने दस्तक दी। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से जहां पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं पहली ही बारिश ने नगर निगम की बरसात पूर्व तैयारियों की पोल भी खोल दी। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल कॉलेज रोड पर भारी जलभराव होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई। पानी भरने के कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को लंबी जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। कॉलेज रोड पर बारिश का पानी भर जाने से वाहन रेंगते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई, जबकि स्कूली छात्र-छात्राओं, ऑटोवाहकों और पैदल राहगीरों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा। सड़क पर पानी जमा होने से कई स्थानों पर वाहन चालकों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कॉलेज रोड पर जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी है। हर बरसात



में यही हालात बनते हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों के अनुसार नालियों की पर्याप्त गहराई और चौड़ाई नहीं होने, जल निकासी व्यवस्था कमजोर होने तथा कई स्थानों पर नालियों पर अतिक्रमण होने के कारण बारिश का पानी समय पर नहीं निकल पाता और पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है। कॉलेज रोड शहर का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां कई स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। प्रतिदिन हजारों लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। ऐसे में बारिश के दौरान जलभराव होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और लंबे जाम की स्थिति बन जाती है।

एनसीएल अमलोरी परियोजना में ड्रिल मशीन में भीषण आग, करोड़ों की मशीन जलकर खाक

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

आज की जनधारा
सिंगरौली। सिंगरौली जिले के नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की अमलोरी परियोजना में शनिवार को एक बड़ा औद्योगिक हादसा सामने आया। परियोजना के तुरां सीम फॉल्ट क्षेत्र में कार्यरत ड्रिल मशीन क्रमांक-9 में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करोड़ों रुपये मूल्य की मशीन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में किसी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि मशीन के नष्ट होने से परियोजना को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के समय ड्रिल मशीन खदान के ऐसे हिस्से में कार्य कर रही थी, जहां तक अग्निशमन वाहन की पहुंच संभव नहीं थी। कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते पूरी मशीन आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। घटना के बाद परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन प्रणाली को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि मशीन ऐसे क्षेत्र में संचालित की जा रही थी, जहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती थी, तो वहां वैकल्पिक अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन सुरक्षा संसाधन उपलब्ध होने चाहिए थे।



हालांकि, इस संबंध में परियोजना प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय सूत्रों का यह भी कहना है कि अमलोरी परियोजना में पूर्व में भी सुरक्षा संबंधी घटनाएं सामने आती रहीं हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिंगरौली यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 28-29 जून 2026 की मध्यरात्रि शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर औचक वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए 10 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक पिशाज के.एम. (भा.पु.से.) के निदेश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस की टीम ने ब्रेथे एनालाइजर के माध्यम से चालकों की जांच की। जांच में शराब के प्रभाव में वाहन चलाते पाए गए सभी चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए प्रक्रण



संबंधित परिवहन विभाग को भेजे जाएंगे। यातायात पुलिस के अनुसार, जनवरी से जून 2026 तक जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 100 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा अब तक 11.50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। पुलिस का कहना है कि सहायता लें। वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, जिससे चालक के साथ-साथ अन्य लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसी कारण इस प्रकार के

अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्होंने शराब का सेवन किया है तो स्वयं नचलाने न चलाएं। इसके बजाय टैक्सी, कैब, सार्वजनिक परिवहन या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की सहायता लें। पुलिस का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।

कागजों में बंद हुए अहाते, हकीकत में शराब दुकानों के पास खुलेआम परोसी जा रही शराब

आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में शराब दुकानों के साथ संचालित होने वाले अहातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। उद्देश्य यह था कि शराब दुकानों के आसपास बैठकर शराब पीने की प्रवृत्ति समाप्त हो, कानून-व्यवस्था बेहतर रहे और आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों को असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन सिंगरौली जिले में जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। शहर की कई शराब दुकानों के आसपास आज भी कथित रूप से खुलेआम अहातों का संचालन किया जा रहा है, जहां सुबह से देर रात तक लोगों के बैठकर शराब पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन स्थानों पर न केवल टेबल और



कुर्सियां लगाई गई हैं, बल्कि पंखा, कुलर, पानी और वेज-नॉनवेज चखने की भी व्यवस्था की गई है। स्थिति ऐसी है कि शराब की दुकान आगे दिखाई देती है और उसके पीछे या बगल में अस्थायी टिनशेड अथवा अन्य स्थानों पर बैठकर शराब सेवन कराया जाता है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसे अहाते आखिर किसके संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। सुबह से देर रात तक सहित कई क्षेत्रों में संचालन के

अनुसार कई शराब दुकानों के पास सुबह दुकान खुलने के साथ ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो देर रात तक जारी रहता है। शराब पीने वालों की भीड़ के कारण आसपास रहने वाले परिवारों, महिलाओं और राहगीरों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार शराब के नशे में विवाह और अभद्र व्यवहार की शिकायतें भी सामने आती हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित होता है। नवानगर सहित कई क्षेत्रों में संचालन के

आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के अधिकांश शराब दुकानों के आसपास स्पष्ट तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। विशेष रूप से नवानगर स्थित शराब दुकान के समीप कथित रूप से बैठकर शराब पीने की पूरी व्यवस्था संचालित होने का आरोप लगाया जा रहा है। यहां टेबल-कुर्सी, कुलर, पंखे के साथ खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लोगों का दावा है कि यह व्यवस्था लंबे समय से संचालित है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं नियम प्रदंश सरकार ने वर्ष 2023 में नई आबकारी नीति लागू करते हुए शराब दुकानों से जुड़े अहातों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। नियमों के अनुसार किसी भी शराब दुकान के भीतर या उसके आसपास बैठकर शराब पीने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके अलावा दुकान परिसर या उसके आसपास भोजन, चखना

अथवा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई, जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। कार्रवाई नहीं होने से उठ रहे सवाल प्रतिबंध के बावजूद कथित रूप से खुलेआम संचालित हो रहे इन अहातों को लेकर आबकारी विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली की भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नियमित निरीक्षण किया जाए तो ऐसे मामलों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके बावजूद अब तक व्यापक स्तर पर कार्रवाई नहीं होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। स्थानीय लोगों ने की संख्या कार्रवाई की मांग स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से मांग की है कि जिले की सभी शराब दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कराया जाए।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सिंगरौली पुलिस लगातार कार्रवाई

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सिंगरौली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना सरई अंतर्गत चौकी निवास और चौकी बरका पुलिस ने सोमवार को अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए। पुलिस ने कुल 10 लाख 60 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पिशाज के.एम., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं एम्सडीओपी देवसर डॉ. गावत्री तिवारी के निर्देशन में की गई। गोपद नदी से हो रहा था अवैध रेत परिवहन पुलिस के अनुसार 29 जून को चौकी निवास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हर्दा स्थित गोपद नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी के नेतृत्व में



पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान दो बिना नंबर के महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत का परिवहन करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने दोनों वाहनों सहित रेत को मौके पर ही जब्त कर लिया। जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत 5 लाख 50 हजार रुपये तथा रेत की कीमत लगभग 5 हजार रुपये आंकी गई है। इस मामले में अपराध क्रमांक 089/2026 एवं 090/2026 दर्ज कर धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं 4/21 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बरका चौकी पुलिस ने भी पकड़ा रेत से भरा ट्रैक्टर इसी दिन देर रात चौकी बरका पुलिस ने गरात के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक और कार्रवाई की।

सरई नगर परिषद सरई के वार्ड क्रमांक 14 में निमाणाधीन नाली को लेकर विवाद गहराया

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के सरई नगर परिषद सरई के वार्ड क्रमांक 14 में निमाणाधीन नाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी राशि से कराए जा रहे इस कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में सोमेट और सरिया की मात्रा कम तथा रेत का अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नाली की सोलिंग, दीवारों की मोटाई, गहराई और चौड़ाई भी स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं बनाई जा रही है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही समय में नाली क्षतिग्रस्त हो सकती है और बरसात में जल निकासी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। निगरानी के अभाव में ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कार्य करा रहा है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। वार्डवासियों ने नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी



(सीएमओ), संबंधित इंजीनियरों और जिला प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने निर्माण सामग्री की प्रयोगशाला से जांच कराए जाने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी उठाई है। नागरिकों का कहना है कि जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता को रोका जा सके। उनका कहना है कि विवासियों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

स्वच्छता का संदेश या पढ़ाई में व्यवधान? NCL के जागरूकता अभियान पर उठने लगे सवाल

निगाही क्षेत्र में स्कूली बच्चों से निकाली गई स्वच्छता रैली, लोगों ने पूछा—क्या यह जिम्मेदारी केवल बच्चों की है

आज की जनधारा

सिंगरौली। स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एनसीएल के निगाही क्षेत्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्कूली बच्चों की सहभागिता से जागरूकता रैली एवं नुककड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को स्वच्छता अपनाने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का संदेश दिया। हालांकि इस आयोजन के बाद अब इसकी कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना निश्चित रूप से सराहनीय पहल है, लेकिन इसके लिए स्कूली बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होना उचित नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि विद्यालय का समय शिक्षा के लिए निर्धारित होता है और ऐसे



आयोजनों के कारण विद्यार्थियों की कक्षाएं बाधित होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि यदि एनसीएल के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन स्वयं संरक्षण जैसे स्वच्छता और पर्यावरण स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाते या नुककड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते, तो उसका संदेश अधिक प्रभावी होता। इससे समाज में यह उदाहरण भी स्थापित होता कि स्वच्छता

केवल बच्चों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। हालांकि कर्मचारी, कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन स्वयं संरक्षण जैसे स्वच्छता और पर्यावरण स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाते या नुककड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते, तो उसका संदेश अधिक प्रभावी होता। इससे समाज में यह उदाहरण भी स्थापित होता कि स्वच्छता

केवल बच्चों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। हालांकि कर्मचारी, कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन स्वयं संरक्षण जैसे स्वच्छता और पर्यावरण स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाते या नुककड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते, तो उसका संदेश अधिक प्रभावी होता। इससे समाज में यह उदाहरण भी स्थापित होता कि स्वच्छता

स्कूल चलें हम उत्सव में कलेक्टर ने विद्यार्थियों को किया प्रेरित, लक्ष्य आधारित शिक्षा और एआई के सकारात्मक उपयोग पर दिया जोर

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैदुन में सोमवार को प्रवेश उत्सव हस्तकल चले हम्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर गौरव बैनल ने विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं से संवाद किया और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने, अनुशासित जीवन अपनाने तथा शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के लक्ष्य, पसंदीदा विषय, करियर विकल्प और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक अपनी जिज्ञासाएं साझा कीं, जिनका उन्होंने सगत और प्रेरक ढंग से समाधान किया। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करें तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर



पर विषयों की मजबूत समझ भविष्य में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आधार बनती है। विद्यार्थियों को विना किसी भय और तनाव के एकाग्रता के साथ अध्ययन करने तथा प्रतिदिन नियमित पढ़ाई की आदत विकसित करने का सलाह भी उन्होंने दी। संवाद के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों को बताया कि विद्यालय परिसर में कॉंप्यूटर सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मद के तहत नैट एवं आईआईटी-जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क

कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से इन कक्षाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर ने पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सकारात्मक और जिम्मेदार उपयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय तकनीक आधारित शिक्षा का है और एआई की सहायता से विद्यार्थी कठिन विषयों को सरलता से समझ सकते हैं, अपनी शंकाओं का

समाधान प्राप्त कर सकते हैं तथा नई जानकारीयें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में केवल रोजगार पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला बनने का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा भी दी। कलेक्टर ने विद्यालय प्रबंधन को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नियमित करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने, विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की जानकारी उपलब्ध कराने तथा विद्यालय में एक समृद्ध एवं सुव्यवस्थित लाइब्रेरी विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तकों के साथ सामान्य ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, व्यक्तित्व विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रेरणादायक पुस्तकों की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों में अध्ययन और पठन-पाठन की रुचि बढ़े। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी, विद्यालय के प्राचार्य संतोष देव पाण्डेय, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बारिश से पहले 84 जर्जर निजी भवन बने जानलेवा खतरा

नगर निगम और जिला प्रशासन की सुस्ती पर उठे सवाल

नोटिस जारी होने के बावजूद कार्रवाई की रफ्तार धीमी, बारिश में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

गोपाल देवकर

बुरहानपुर। शहर में मानसून की दस्तक के साथ ही जर्जर निजी भवनों का खतरा भी बढ़ गया है। नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे में शहर के 84 निजी मकान और भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। निगम ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर उन्हें स्वयं भवन हटाने अथवा सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकांश भवन अब भी खतरनाक स्थिति में खड़े हैं। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं कि जब खतरे की जानकारी पहले से थी तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

84 जर्जर भवनों की पहचान, नोटिस के बाद भी कार्रवाई अधूरी

नगर निगम के अनुसार शहर में 84 निजी जर्जर भवनों को चिह्नित किया गया है। इन भवनों के मालिकों को नोटिस देकर भवन हटाने या सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम का दावा है कि दो जर्जर भवनों को हटाया जा चुका है, जबकि



कुछ अन्य भवनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अधिकांश भवन अब भी लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश से पहले केवल नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई बेहद धीमी रहती है।

जनहानि रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर भवनों का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन और भवन मालिकों दोनों की जिम्मेदारी है कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं। शहरवासियों का कहना है कि कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर तत्काल प्रभाव से खतरनाक भवनों को हटाया जाए, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी परिवार को हादसे का शिकार न होना पड़े।

बारिश के दौरान जर्जर भवनों की दीवारें और छतें कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनके गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे भवनों के आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। शहरवासियों का कहना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई कर ऐसे भवनों को हटाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जर्जर भवनों की पहचान कर नोटिस जारी किए गए हैं और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि प्रशासन के पास जर्जर भवनों की सूची उपलब्ध है। जिन भवनों को नोटिस दिए जा चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और जिन भवनों को अभी नोटिस नहीं दिए गए हैं, उन्हें भी जल्द नोटिस जारी कर नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कंग्रेस ने प्रशासन को घेरा, तत्काल कार्रवाई को मांग कर कंग्रेस जिलाध्यक्ष रिकू टाक ने नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में कई जर्जर भवन ऐसे हैं जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन हर वर्ष नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन भवनों को नहीं हटाया गया तो किसी भी दिन जनहानि हो सकती है। रिकू टाक ने बताया कि वे स्वयं कलेक्टर से मिलकर शहर के सभी खतरनाक जर्जर भवनों को तत्काल हटाने की मांग करेंगे।



बारिश में बढ़ जाता है खतरा, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल : केंद्रीय मंत्री नड्डा

केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलें

मध्यप्रदेश को पीएम-केयर्स के तहत आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों की सौगात

आज की जनधारा

भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। शुभारंभ की गई प्रमुख पहलों में आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान ऐप, आयुष्मान सारथी क्लाउडसर्विसेस (एनएचएसएस), युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई), ई-सुश्रुत क्लिनिक, ड्रा रिजिस्ट्री, कॉमन कोड्स फॉर इंडिया (सीएसीआई) तथा भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विसेस (बीएचटीएस) शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि 90 करोड़ से अधिक आभा खाते और 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनने के साथ भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु 2.0 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों सहित सभी आयु वर्ग के नागरिकों



को एक ही मंच पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार, आयुष) प्रतापरव जाधव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मती अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. एम. निवास, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव मती पुण्य सलिला वास्तव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव एवं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल तथा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश को पीएम-केयर्स के तहत आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरणों की सौगात मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। इसके तहत आगामी तीन वर्षों में पीएम-केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई-स्कैनर हैडहेल्ड एक्स-रे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान (डायग्नोस्टिक) सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रतापरव नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम-केयर्स के माध्यम से उपलब्ध होने वाले अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देंगे तथा विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

थाना बिरलाग्राम पुलिस ने टापरी पर आपसी विवाद में की हत्या के आरोपी को 24 घंटों के भीतर किया गिरफ्तार

आज की जनधारा

28.06.2026 को फरियादी आकाश पिता गोविन्द उम्र 26 वर्ष निवासी जी ब्लाक टापरी बिरलाग्राम ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि जयप्रकाश उर्फ टक्कु, राजेश राठी, किशोर कछवा, रवि नायक और रवि परमार राजेश राठी की टापरी पर बैठे थे जहां पर मोहन डोली निवासी ई ब्लाक टापरी का भी था और वीर विशालसिंह दोनों राजेश राठी की टापरी पर जाकर खड़े हो रहे थे इतने में मोहन डोली निवासी ई ब्लाक टापरी बिरलाग्राम नागदा का जयप्रकाश उर्फ टक्कु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद होने पर मोहन जयप्रकाश को गालियां देने लगा, और जयप्रकाश ने मोहन को गालियां देने से मना किया तो मोहन चिल्लावांट करते हुये अपने घर तरफ गया और तलवार लेकर आया और जयप्रकाश पर तलवार से वार किया, फिर मैं और अन्य साथी स्टुटी पर बिठाकर जनसेवा अस्पताल बिरलाग्राम नागदा लेकर गये जहां पर डाक्टर द्वारा ईलाज के दौरान चेक



कर बताया कि जयप्रकाश की मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट से अप.क्र. 195/2026 धारा-103(1) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस कार्यवाही - अपराध हत्या का होकर गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण करणदीप सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक नागदा विक्रम अहिरवार द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम बनाकर विवेचना प्रारंभ की गई एवं महज 24 घंटों के अंदर ही आरोपी मोहन पिता अंबाराम उम्र 45 वर्ष निवासी ई ब्लाक टापरी बिरलाग्राम नागदा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्यवाही- थाना प्रभारी बिरलाग्राम उनि.जितेन्द्र पाटीदार, सजिन भुरिया मोहरे, प्र.आर. गणेश पाल, आर. संदीप यादव, आर. नटवरसिंह, आर. अंकित पांचाल, आर. सौदागर जाट, आर. आनन्दसिंह, आर. हेमराजगुर्जर, म.आर.निबिया, म.आर शिवानी की मुख्य भूमिका रही।

जावरा में बिखरे दक्षिण भारत के रंग: जैन सोशल ग्रुप जावरा मैत्री परिवार के मद्रासी थीम ने जीता सबका दिल

आज की जनधारा

जावरा (निप) मिलकर जब कदम बढ़ाते हैं तो इतिहास बन जाता है इस कहावत को सच करते हुए जैन सोशल ग्रुप जावरा मैत्री परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हर आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जावरा शहर की शान बन जाता है। मैत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बार ग्रुप ने मद्रासी थीम पर आधारित एक बेहद अनूठा और भव्य आयोजन किया जिसने मैत्री परिवार के दंपति साथियों को सीधे दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सफर पर ले जाने का अहसास कराया है। उक्त विचार अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर अनिल धारीवाल ने व्यक्त किये उक्त मौके पर नेचुरल अवरनेस कमेटी के चेयरमैन संदीप राक ने कहा कि हमारी अमूल्य ताकत हमारा टीम वर्क है मैत्री परिवार का यह शानदार आयोजन इस बात का गवाह है कि जब पूरा परिवार एक दिशा



में कदम बढ़ाता है, तो इतिहास खुद-ब-खुद बन जाता है हमारी भारतीय 7परंपरानुसार स्वाद और संस्कृति का अनूठा संगम इस विशेष उत्सव में चारों तरफ पारंपरिक दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। वेशभूषा से लेकर सजावट तक हर चीज में मद्रासी संस्कृति का जीवंत रूप नजर आया जो निश्चित रूप से

मैत्री परिवार के सदस्यों कि सामूहिक मेहनत से सफलता पुर्वक आयोजन के लिए पूरी टीम को साधुवाद। ग्रुप के अध्यक्ष संदीप श्रीमाल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यहाँ वेशभूषा के साथ मद्रासी व्यंजन बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक भोजन रहा जिसने आप हृष्ट सभी दंपति साथियों का दिल जीत लिया। इस बेमिसाल और सफल आयोजन के सफलता के पीछे समस्त दंपति और टीम वर्क का जादू इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता का श्रेय किसी एक को नहीं बल्कि पूरी मैत्री परिवार की टीम को जाता है जिसके लिए सभी दंपति साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। उक्त जानकारी देते हुए ग्रुप के प्रचार सचिव मनीष मेहता ने बताया कि ग्रुप द्वारा नगर में प्रथम बार मद्रासी थीम पर आयोजित आयोजन में प्रवेश से लेकर ड्रेसउप, सजावट, भोजन, आदि समस्त पारंपरिक रहा है।

नरसिंहगढ़ में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से चिंता, युवाओं का भविष्य दांव पर

आज की जनधारा

नरसिंहगढ़। क्षेत्र में नशीले पदार्थों के कथित बढ़ते कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरी चिंता व्याप्त है। रहवासियों का कहना है कि नगर एवं आसपास के कुछ क्षेत्रों में युवाओं और किशोरों के बीच नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई किशोर और युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नागरिकों का आरोप है कि नशे की लत के चलते कुछ युवाओं का व्यवहार आक्रामक हो रहा है तथा क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि घरों से मोबाइल, लैपटॉप, ओजार्, जूते-चपल सहित अन्य सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नागरिकों का यह भी कहना है कि नगर के कुछ इलाकों एवं आसपास के क्षेत्रों में कथित रूप से गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ा जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल



पुलिस कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि नशामुक्ति अभियान, जनजागरूकता कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेज स्तर पर परामर्श और परिवारों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो युवा पीढ़ी का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। क्षेत्र के नागरिकों ने पुलिस एवं प्रशासन से मांग की है कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी की शिकायतों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को नशे की गिरफ्तार से बाहर निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

राउंड टेबल इंडिया 347 ने किया फ्रीडम थू एजुकेशन- तीन क्लासरूम का लोकार्पण

आज की जनधारा

भोपाल। राउंड टेबल इंडिया 347 द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बिजली कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल में फ्रीडम थू एजुकेशन तीन क्लासरूम परियोजना का लोकार्पण किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखना है। कार्यक्रम में P&G मध्य प्रदेश के CSR HEAD संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही एरिया-17 होनोरीरी टेबलर अभिषेक जैन, अफए17 के चेयरमैन उमंग अग्रवाल मौजूद थे। विद्यालय की प्रारंभिक पर्याप्त मंडल में आयोजन के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए राउंड टेबल इंडिया 347 ने उनका विशेष आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भोपाल एलीट राउंड टेबल 347 के चेयरमैन अंकुर बड़कुर,



वाइस चेयरमैन अखिल केसवानी, सेक्रेटरी श्रेय अरोरा, ट्रेजरर नितेश अरोरा सहित BERT 347 के सभी टेबलर सहयोगियों के अंत में भोपाल एलीट राउंड टेबल के project के सहयोग LMF विशाल जैन अजयरा ने सभी अतिथियों, विद्यालय परिवार, सहयोगियों एवं टेबलर सहयोगियों का निष्पक्ष एवं सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए राउंड टेबल इंडिया 347 ने उनका विशेष आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भोपाल एलीट राउंड टेबल 347 के चेयरमैन अंकुर बड़कुर,

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बावड़ी उत्सव का आयोजन, जल संरक्षण का दिया संदेश

आज की जनधारा

उज्जैन। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड उज्जैन द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 28 जून को श्री चिंतामण गणेश मंदिर परिसर में जनजागृति कार्यक्रम एवं बावड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल संवर्धन के प्रति जनजागरण करना था। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश सिंदल, भाजपा मंडल महामंत्री जितेंद्र आंजना, चिंतामण गणेश मंदिर समिति सदस्य यशवंत पटेल, कार्तिकेय मिश्रा प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा महेंद्र जायसवाल मीडिया प्रभारी विकासखंड समन्वयक अरुण व्यास मंदिर के पुजारी गणेश शर्मा, प्रशासक अभिषेक शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मनोज डागर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भावाना श्री गणेश के पूजन-अर्चन एवं दीप



प्रचलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत डॉ. शैलत कुमार शर्मा, मदनलाल तिलोरिया, विक्रमसिंह अजाना, श्याम उपाध्याय, भरत आंजना, संजय आंजना, नितिन त्रिवेदी, संजय चौहान, राहुल सिंह एवं परामर्शदाता सुनील बाराड़ द्वारा किया गया। स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा विकासखंड

समन्वयक अरुण व्यास ने प्रस्तुत की। अपने संबोधन में सतीश सिंदल ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्राचीन बावड़ियों और जल स्रोत हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। श्री गणेश शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल को जीवन एवं आस्था का आधार माना गया है। जल स्रोतों का संरक्षण करना धर्म, संस्कृति और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यशवंत पटेल ने कहा कि समाज की सहभागिता से ही जल संरक्षण अभियान सफल हो सकता है। उन्होंने युवाओं से प्राचीन जल

संरचनाओं के संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री चिंतामण गणेश मंदिर परिसर स्थित प्राचीन लक्ष्मण बावड़ी पर दीपमालाएं सजाकर पूजन-अर्चन एवं महाआरती की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था से श्रीमती कविता शर्मा, कोस्तुभ शर्मा, ग्राम विकास प्रस्पुटन समितियों के सदस्य तथा लोकोडा एवं चिंतामण गणेश सेक्टर के जितेंद्र सिंह परिहार सूरज पांचाल मखन आंजना राहुल परिहार जितेंद्र ठक्कर भगत पटेल पवन चौधरी ईश्वर चौहान विक्रम सिंह आंजना आदि ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि डॉ. राजेश रावल 'सुशील' ने किया तथा अंत में श्री-नवांकुर संस्था के अध्यक्ष डॉ. शैलत कुमार शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री सिद्ध चक्र विधान का सार्थक समापन श्रद्धालुओं ने लिए अनेक संकल्प विश्व शांति महायज्ञ कि आहुति में अपनी अपनी बुराइयों को भी दूर किया

आज की जनधारा

भोपाल। श्री महावीर जैन मंदिर वर्धमान नगर दाता कालोनी में आठ दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर 1024 अरघा अर्पित हुए, विश्व शांति के लिए हवन कुंड में आहुतियां दी गईं, अनुष्ठान के समापन पर धार्मिक आयोजन की सार्थकता दिखाई दी जब युवक युवतियों ने सादगी के साथ समाज में विवाह का संकल्प लिया, बच्चों ने फास्ट फूड का त्याग, और अनेक लोगों द्वारा हवन कुंड की आहुति में अपनी अपनी बुराइयों को त्याग किया, आयोजक परिवार श्रीमती मालती नवीन सिंहाल जैन दिगंबर परिवार अर्चना कर विधान अंशेषक पूजा द्रव्य श्रीफल अर्पित किए प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया आकर्षक मंडल कि परिभाषा दी प्रतिष्ठाचार्य प्रकाश छोटू भैया ने कहा अनुष्ठान में पुण्य की जगह यहाँ भावना होना चाहिए हमसे किसी का बुरा न हो, हम सभी अपनी सामाजिक सरोकार



के कार्य, अपने शहर को स्वच्छ सुंदर रखें, मैं इंधन इंद्राणियों द्वारा अनुष्ठान के दौरान अंशेषक पूजा अर्चना कर विधान अंशेषक पूजा द्रव्य श्रीफल अर्पित किए प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया आकर्षक मंडल कि परिभाषा दी प्रतिष्ठाचार्य प्रकाश छोटू भैया के निर्देशन में प्रमुख पात्र नवीन सिंहाल सो धर्म

इंद्र दीक्षा प्रतीक श्री पाल मेना सुंदरी श्रीमती मालती दिशा चंदना ध्वजारोहण करता सुनीता प्रमोद कुबेर मंडल वीरेंद्र शहीन विजय विनोद अनिल महावीर तनु जैन निमिता विकास ने मंडल पर श्रीफल अर्पित कर सभी के मंगल मय जीवन की कामना जगत में शांति की कामना की।

तिरछी नज़र से

जीडीपी का जादू, जेब का जुगाड़



प्रभातदत्त झा

सुधी पाठकों, पिछले दिनों एक खबर आई कि देश की जीडीपी सात दशमलव सात प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ रही है। यह सुनकर हमारे मोहले के पंडित जुगल किशोर इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी साइकिल की चेन तक तेल पिला दी-सोचा, अब तो रफ्तार ही रफ्तार है। मगर जब वे सब्जी खरीदने बाजार गए और आलू-प्याज के भाव सुने, तो उनकी रफ्तार वहीं ठहर गई। बोले, "यह जीडीपी कहीं और दौड़ रही है, मेरी थैली तो वहीं खड़ी है, जहाँ पिछले साल थी।"

दरअसल सरकार ने इस बार जीडीपी मापने का तरीका ही बदल दिया है। नया आधार वर्ष आया है- 2022-23- और उसमें अब जीएसटी नेटवर्क का डेटा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और घरों में काम करने वाले रसोइए, ड्राइवर व नौकरों की सेवाएँ भी शामिल कर ली गई हैं। मतलब अब अगर आपके घर में खाना बनाने वाली मेहरारू भी काम करती है, तो वह भी जीडीपी में अपना योगदान दे रही है- बिना यह जाने कि उनकी मेहनत किसी आँकड़े में 'ग्रोथ' बनकर मंत्रालय की फाइलों में चमक रही है, जबकि उनकी अपनी तनख्वाह वहीं की वहीं अटक है, जहाँ तीन साल पहले थी।

यह वैसा ही है जैसे कोई गृहिणी रसोई में आटे की क्रीम बढ़ने पर परेशान हो, और उसका पति अखबार पढ़कर कहे, "चिंता क्यों करती हो, देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुँच गई।" गृहिणी पूछे, "चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुँची, तो पाँचवें नंबर पर हमारा महीने का राशन कब पहुँचेगा?" पति निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि आँकड़ों की भाषा और रसोई की भाषा में अनुवादक अभी तक नियुक्त नहीं हुआ।

भाइयों और बहनों, यही वह जादू है जो हमारे आर्थिक पंडित बरसों से दिखाते आए हैं। जीडीपी बढ़ती दिखानी हो तो आधार वर्ष बदल दो, परिभाषा बदल दो, टोकरी में नई चीजें डाल दो-जैसे कोई जादूगर खाली टोपी में रुमाल डालकर कबूतर निकाल दे। दर्शक तालियाँ बजाते हैं, यह सोचे बिना कि कबूतर पहले से जादूगर की जैकेट में बैठा था।

इधर विश्व बैंक ने भी अपनी राय दे दी है कि आने वाले साल में हमारी रफ्तार घटकर साढ़े छह प्रतिशत के आसपास सिमट जाएगी, क्योंकि तेल और ऊर्जा की कीमतें आम आदमी की जेब पर पहले से ज्यादा बोझ डाल रही हैं। यानी एक तरफ मंत्रालय कह रहा है कि हम दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर खड़ा आम नागरिक हिसाब लगा रहा है कि इस महीने बाइक में तेल भरवाए या बच्चे की फ़िस जमा करे।

पंडित जुगल किशोर का मानना है कि असली जीडीपी वही है जो उनकी जेब में महीने के आखिर में बचती है-और वह आँकड़ा पिछले दस साल से लगातार ऋणात्मक चल रहा है। उन्होंने एक नायाब सुझाव भी दिया है-सरकार को चाहिए कि अगली बार जीडीपी मापते समय उसमें यह भी शामिल करे कि आम आदमी की मुस्कान कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी। उस आँकड़े में, उनका दावा है, हम शायद माइंस में चले जाएँ।

बहरहाल, जीडीपी की दौड़ जारी है, और हम सब उसके तमाशबीन हैं-कभी ताली बजाते, कभी अपनी जेब टटोलते। फर्क सिर्फ इतना है कि दौड़ में मेडल किसी और के यत्ने में पड़ रहा है, और हाँफना हमारे हिस्से में आया है।

देवेंद्रनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

उन्होंने एक नायाब सुझाव भी दिया है-सरकार को चाहिए कि अगली बार जीडीपी मापते समय उसमें यह भी शामिल करे कि आम आदमी की मुस्कान कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी। उस आँकड़े में, उनका दावा है, हम शायद माइंस में चले जाएँ।

बहरहाल, जीडीपी की दौड़ जारी है, और हम सब उसके तमाशबीन हैं-कभी ताली बजाते, कभी अपनी जेब टटोलते। फर्क सिर्फ इतना है कि दौड़ में मेडल किसी और के यत्ने में पड़ रहा है, और हाँफना हमारे हिस्से में आया है।

देवेंद्रनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

उन्होंने एक नायाब सुझाव भी दिया है-सरकार को चाहिए कि अगली बार जीडीपी मापते समय उसमें यह भी शामिल करे कि आम आदमी की मुस्कान कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी। उस आँकड़े में, उनका दावा है, हम शायद माइंस में चले जाएँ।

बहरहाल, जीडीपी की दौड़ जारी है, और हम सब उसके तमाशबीन हैं-कभी ताली बजाते, कभी अपनी जेब टटोलते। फर्क सिर्फ इतना है कि दौड़ में मेडल किसी और के यत्ने में पड़ रहा है, और हाँफना हमारे हिस्से में आया है।

देवेंद्रनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

उन्होंने एक नायाब सुझाव भी दिया है-सरकार को चाहिए कि अगली बार जीडीपी मापते समय उसमें यह भी शामिल करे कि आम आदमी की मुस्कान कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी। उस आँकड़े में, उनका दावा है, हम शायद माइंस में चले जाएँ।

बहरहाल, जीडीपी की दौड़ जारी है, और हम सब उसके तमाशबीन हैं-कभी ताली बजाते, कभी अपनी जेब टटोलते। फर्क सिर्फ इतना है कि दौड़ में मेडल किसी और के यत्ने में पड़ रहा है, और हाँफना हमारे हिस्से में आया है।

उच्च न्यायालय में सीधी वकालत, न्याय प्रणाली के लिए वरदान या अभिशाप?



डॉ. निधि गुप्ता

(पी. एच.डी., एम.लिव., एल.एल.बी., बी.एस.सी.)

प्रस्तावना

भारतीय न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता को 'ऑफिसर ऑफ़ द कोर्ट' कहा जाता है। कानून की डिग्री (LLB) प्राप्त करना एक उपलब्धि है, लेकिन वकालत एक ऐसा कौशल है जो केवल अनुभव की भट्टी में तपकर ही निखरता है। वर्तमान में एक गंभीर प्रवृत्ति देखी जा रही है-युवा विधि स्नातक बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के सीधे उच्च न्यायालय (High Court) में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल न्याय की गुणवत्ता बल्कि स्वयं अधिवक्ताओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है।

अनुभवहीनता का संकट और संभावित नुकसान

उच्च न्यायालय मुख्य रूप से संवैधानिक और अपीलारी न्यायालय है। यहाँ सीधे वकालत करने से कई गंभीर चुनौतियाँ पैदा होती हैं: **जमीनी हकीकत से दूरी**: एक मुकदमे के केस की नींव निचली अदालतों (Trial Courts) में रखी जाती है, जहाँ गवाही, साक्ष्य (Evidence) और जिरह (Cross-examination) की प्रक्रिया होती है। जो वकील सीधे उच्च न्यायालय पहुँचते हैं, वे



अक्सर केस की फ़हल की तकनीकी बनावट और साक्ष्यों के विश्लेषण में विफल रहते हैं। **प्रक्रियात्मक और ड्राफ़्टिंग त्रुटियाँ**: उच्च न्यायालय में रिट याचिका और अपीलों के अपने सख्त नियम होते हैं। अनुभव की कमी के कारण अक्सर कमजोर ड्राफ़्टिंग की जाती है, जिससे न केवल मुकदमे का नुकसान होता है, बल्कि न्यायालय का कीमती समय भी बर्बाद होता है। **आत्मविश्वास और शिष्टाचार का अभाव**: वरिष्ठ न्यायाधीशों के सामने कानूनी तर्कों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मानसिक परिपक्वता और कोर्ट रूम प्रोटोकॉल की गहरी समझ चाहिए, जो केवल डिग्री के अध्यास से आती है।

भविष्य के लिए प्रस्तावित सख्त और उन्नत सुधार

न्याय प्रणाली की गरिमा बनाए रखने के लिए अब केवल डिग्री काफी नहीं है। समय की मांग है कि उच्च न्यायालय में वकालत के लिए कुछ कड़े 'फ़िल्टर' और मानक तय किए जाएँ: **अनिवार्य निचली अदालत का अनुभव**: नियम बनाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय में

स्वतंत्र प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 से 5 वर्ष का अनुभव जिला या सत्र न्यायालयों में अनिवार्य हो। इससे वकील को केस की जड़ (Ground Reality) समझ आएगी। **'हार्ड कोर्ट प्रैक्टिस' परीक्षा (AOR की तर्ज पर)**: जैसे सुप्रीम कोर्ट में 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' (AOR) की परीक्षा होती है, वैसे ही प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी एक योग्यता परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। यह परीक्षा केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक ड्राफ़्टिंग और नवीनतम केस-लॉ पर आधारित हो।

अनिवार्य ट्यूटोरियल (Pupillage) और मेंटरशिप: ब्रिटेन की तर्ज पर, नए वकीलों के लिए कम से कम एक साल किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ 'ट्रेनिंग पीरियड' अनिवार्य होना चाहिए। इस दौरान उनके आचरण और सीखने की प्रगति का ऑडिट बार काउंसिल द्वारा किया जाए। **डिजिटल साक्षरता और विशेषज्ञता (Specialization)**: आधुनिक समय में ई-फ़ाइलिंग और एआई-आधारित रिसर्च अनिवार्य है। उच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए 'डिजिटल

दक्षता टेस्ट' और विशिष्ट कानूनों (जैसे टैक्स, क्रिमिनल या संवैधानिक कानून) में विशेषज्ञता प्रमाण-पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। **प्रो-बोनो कार्य का कोटा**: अनुभव के प्रमाण के रूप में, युवा वकीलों को उच्च न्यायालय आने से पहले निचली अदालतों में कम से कम 5 से 10 केस गरीबों के लिए (मुफ्त) लड़ने का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय 'सीखने की जगह' (Learning Ground) नहीं, बल्कि 'प्रोफेशनल ग्राउंड' होना चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर बिना इंटरशिप और अनुभव के सीधे सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरह एक वकील को बिना जमीनी अध्यास के सीधे उच्च न्यायालय में पैरवी की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यदि बार काउंसिल और न्यायालिका इन उन्नत सुधारों को लागू करती है, तो इससे न केवल अधिवक्ताओं का स्तर ऊँचा होगा, बल्कि 'न्याय मिलने में देरी' जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा।

धागों में बसते रंग



सुलक्षणा जिल्लार

जब बुनाई से पहले ही तैयार हो जाती है कपड़ों की खूबसूरती

कपड़ों को रंगना सदियों पुरानी कला है, लेकिन वर्कों की दुनिया में एक ऐसी अनोखी तकनीक भी है, जिसमें कपड़ों को नहीं बल्कि धागों को पहले रंगा जाता है, बाद में इन्हें रंगीन धागों से बुना गया कपड़ा अपने आप में अद्भुत डिजाइन और रंगों का संगम बन जाता है। यही तकनीक वर्कों को एक अलग पहचान और कलात्मक सौंदर्य प्रदान करती है। वस्त्र निर्माण की दुनिया में एक बेहद अनोखी और पारंपरिक

तकनीक है। इसमें पहले सूती रेशमी धागों को विभिन्न प्राकृतिक कृत्रिम रंगों से रंगा जाता है। इसके बाद इन रंगीन धागों को विशेष क्रम में करघे में बुना जाता है, जिससे कपड़े पर अद्भुत डिजाइन अपने आप उभर कर सामने आते हैं। इस पारंपरिक सोच और तकनीक को टेक्सटाइल की दुनिया में यान फ़र्ट एप्रोच कहा जाता है। आम कपड़ों में पहले सादा कपड़ा बन जाता है और फिर उसे पर छपाई यांगे की जाती है लेकिन इकत के धागा ही कल का कैनुवस बनता है। धागों से कला के जन्म लेने के इस सफ़र को तीन खूबसूरत पड़ाव में समझा जा सकता है।

1 धागों की गणितीय सोच

2 रंगों का रहस्य

3 करघे पर कल का जन्म

जब इन रंगे हुए धागों को करघे पर चढ़ाया जाता है, तो वह हर एक धागे के जुड़ने से धीरे-धीरे डिजाइन उभरने लगती है। बुनाई के समय धागों के सूक्ष्म खिंचाव से जो धुंधलापन आता है, वही इस कला की असली खूबसूरती और इसकी हस्ताक्षर होने की पहचान है।

आज आधुनिक फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में भी यह डिजाइन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैक्स स्ट्रीक्स और कई प्रीमियम फैब्रिक इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह तकनीक न केवल रंगों की टिकाऊ पर बढ़ती है बल्कि वर्कों को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। धागों में समावेश रंग यह साबित करते हैं कि सृजन की शुरुआत हमेशा अंतिम रूप से नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद से होती है। यही धागे आगे चलकर भारतीय कला संस्कृति और शिल्प कौशल की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रंग कपड़ों पर नहीं पहले धागों पर चढ़ते हैं और वहीं से जन्म होती है बुनाई की असली कला।

आज आधुनिक फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में भी यह डिजाइन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैक्स स्ट्रीक्स और कई प्रीमियम फैब्रिक इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह तकनीक न केवल रंगों की टिकाऊ पर बढ़ती है बल्कि वर्कों को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। धागों में समावेश रंग यह साबित करते हैं कि सृजन की शुरुआत हमेशा अंतिम रूप से नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद से होती है। यही धागे आगे चलकर भारतीय कला संस्कृति और शिल्प कौशल की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रंग कपड़ों पर नहीं पहले धागों पर चढ़ते हैं और वहीं से जन्म होती है बुनाई की असली कला।

आज आधुनिक फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में भी यह डिजाइन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैक्स स्ट्रीक्स और कई प्रीमियम फैब्रिक इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह तकनीक न केवल रंगों की टिकाऊ पर बढ़ती है बल्कि वर्कों को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। धागों में समावेश रंग यह साबित करते हैं कि सृजन की शुरुआत हमेशा अंतिम रूप से नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद से होती है। यही धागे आगे चलकर भारतीय कला संस्कृति और शिल्प कौशल की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रंग कपड़ों पर नहीं पहले धागों पर चढ़ते हैं और वहीं से जन्म होती है बुनाई की असली कला।

आज आधुनिक फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में भी यह डिजाइन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैक्स स्ट्रीक्स और कई प्रीमियम फैब्रिक इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह तकनीक न केवल रंगों की टिकाऊ पर बढ़ती है बल्कि वर्कों को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। धागों में समावेश रंग यह साबित करते हैं कि सृजन की शुरुआत हमेशा अंतिम रूप से नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद से होती है। यही धागे आगे चलकर भारतीय कला संस्कृति और शिल्प कौशल की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रंग कपड़ों पर नहीं पहले धागों पर चढ़ते हैं और वहीं से जन्म होती है बुनाई की असली कला।

आज आधुनिक फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में भी यह डिजाइन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैक्स स्ट्रीक्स और कई प्रीमियम फैब्रिक इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह तकनीक न केवल रंगों की टिकाऊ पर बढ़ती है बल्कि वर्कों को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। धागों में समावेश रंग यह साबित करते हैं कि सृजन की शुरुआत हमेशा अंतिम रूप से नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद से होती है। यही धागे आगे चलकर भारतीय कला संस्कृति और शिल्प कौशल की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रंग कपड़ों पर नहीं पहले धागों पर चढ़ते हैं और वहीं से जन्म होती है बुनाई की असली कला।

हैदराबाद निवेशक कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को 9,580 करोड़ के प्रस्ताव डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, सीमेंट और सोलर सेक्टर में 7,800 नौकरियों के नए अवसर



जी. वी. एन. राजू

12 जून 2026 को हैदराबाद में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित 'इन्वेस्टर्स कनेक्ट' कार्यक्रम में सात प्रमुख कंपनियों ने राज्य में कुल रू. 9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए। इन प्रस्तावों से सीधे तौर पर लगभग 7,800 नौकरियाँ सृजित होने की संभावना है। यह सिर्फ आँकड़ों का खेल नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक खनन-आधारित मॉडल से आगे ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

सबसे बड़ा प्रस्ताव हदपरनेक्ट डेटा सेंटर का रू. 4,200 करोड़ का है, जिससे डेटा सेंटर स्थापित होगा और करीब 250 उच्च-कुशल नौकरियाँ बनेंगी। डिजिटल

इकोनॉमी के युग में डेटा सेंटर राज्य को क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रस्ताव फीग्रेड एंड कंपनी का रू. 2,912 करोड़ का सीमेंट क्षेत्र में है, जिससे 4,000 से अधिक नौकरियाँ मिलने की उम्मीद है। बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ यह प्रस्ताव राज्य की निर्माण गतिविधियों को गति देगा।

निवाह लैब्स का रू. 1,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव सबसे रणनीतिक है। भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ तालमेल बिनाते हुए यह कदम छत्तीसगढ़ को हार्ड-टेक मैनुफैक्चरिंग की ओर ले जा सकता है। एसजी मार्ट का रू. 700 करोड़ का सोलर उपकरण निर्माण प्रस्ताव हरित ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है, जबकि श्री सरवणा मिल्स का रू. 528 करोड़ का टेक्सटाइल प्रस्ताव श्रम-प्रधान उद्योग को मजबूत करेगा (लगभग 2,500 नौकरियाँ)। कबरा ड्रग्स (रू. 200 करोड़, फार्मा) और दिनाशां डेयरी (रू. 40 करोड़, डेयरी प्रोसेसिंग) जैसे प्रस्ताव मूल्य संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया

कि राज्य की नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में राज्य को रू. 8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और नक्सल मुक्त छवि अब उच्च-तकनीकी और हरित उद्योगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है।

हालांकि चुनौतियाँ बाकी हैं। सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी जरूरी है। यदि सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाए और भूमि-जल-बिजली जैसे मूलभूत मुद्दों को समयबद्ध हल करे, तो ये प्रस्ताव वास्तविकता बन सकते हैं।

कुल मिलाकर यह निवेश छत्तीसगढ़ को 'रिसोर्स स्टेट' से 'नॉलेज एंड मैनुफैक्चरिंग स्टेट' की ओर ले जाने का अवसर है। यदि नीतिगत निरंतरता और तेज क्रियान्वयन बना रहा, तो आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक संरचना और रोजगार परिदृश्य दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखेगा। (आर्थिक मामलों के जानकार और मजदूर आंदोलनों को धार देने वाले नेतृत्व)

सर्जिकल रोबोटिक्स में भारत का डंका

एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल को मिला प्रतिष्ठित 'आउटस्टैंडिंग कंपनी' सम्मान

जून 2026 भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी (मेडटेक) क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल को सर्जिकल रोबोटिक्स (एसआरटी) इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 में च्आउटस्टैंडिंग कंपनीज सम्मान से नवाजा गया है। यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि कंपनी का चयन सर्जिकल रोबोटिक्स और इंट्यूइविव, मेड्ट्रॉनिक, जॉनसन एंड जॉनसन मेडटेक, डिस्टलमोशन, मेरिल, माइक्रोपोर्ट, थिंक सर्जिकल,



प्यूटेक और प्रिसिजन आईओ रूप-के बीच से किया गया। इस सम्मान ने वैश्विक सर्जिकल रोबोटिक्स उद्योग में एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल की मजबूत और अग्रणी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है।

अपने चौथे संस्करण में प्रवेश कर चुके सर्जिकल रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी (एसआरटी) इंडस्ट्री अवार्ड्स को सर्जिकल रोबोटिक्स क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में गिना जाता है।

मानसून और गर्मियाँ: बिलासपुर में पक्षियों के जीवन-चक्र के लिए अहम मौसम



राहुल गुप्ता

गर्मी और आने वाला मानसून भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों के जीवन में महत्वपूर्ण दौर हैं, और बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है। इन महीनों में अधिकांश पक्षी प्रजनन के शिखर पर होते हैं। पूर्व-मानसून की बारिश की वजह से कीटों की संख्या में तेज़ वृद्धि होती है - जो कई प्रजातियों का मुख्य आहार है - और यह मात्रा माता-पिता को अपने चूड़ों को पोषित करने में बड़ी मदद देती है।

स्थायी प्रजातियाँ और कुछ आवासी प्रवासी इस मौसमी अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में पैदा होने वाले, ब्लू-नेड मोनार्क, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर और व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर के घोंसले व निम्बर



चूड़ों के दर्शन हो रहे हैं। जमीन पर घोंसला बनाने वाले रेड-वॉटेड और येलो-वॉटेड लेग्विंग भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि ब्लैक-विंग स्ट्रिप्ल, स्मॉल प्रेटिनकोल और ऑरिएण्टल प्रेटिनकोल जैसे वेटलैंड-पक्षी अपने चूड़ों को नाखून और दलदलों पर पाले जा रहे हैं। स्केव्नेजर व कुछ झाड़ी-रहने वाली प्रजातियाँ - मिश्र का गिद्ध, विविध बैबलर व क्यू - भी प्रजनन गतिविधि दिखा रही हैं, जो स्थानीय आवासों की सेहतमंद विविधता का संकेत



है। बगुलों, बगीचों और झाड़ियों में घोंसलों व चूड़ों की स्पष्टता बिलासपुर की समृद्ध एविफैना विविधता और प्रजनन आवासों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरल उपाय - घोंसलों के पास होने वाली गतिविधियों में कमी, कीट नाशकों का सीमित या नियंत्रित उपयोग ताकि शिकार उपलब्ध बना रहे, वेटलैंड्स की रक्षा तथा शोर-गुल करने वाले कामों को प्रजनन अवधि के बालू करना - प्रजनन सफलता बढ़ा सकते हैं।



स्थानीय बर्डवॉचर और निवासी भी मदद कर सकते हैं: समुदायिक समूहों को घोंसलों की जानकारी देना, दूरी बनाए रखते हुए फोटोग्राफ़ी करना और मौसमी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। जैसे-जैसे गर्मी मानसून में बदलती है, बिलासपुर के आसमान और दलदल उड़ना सीखते युवा पक्षियों से जीवंत रहेंगे - यह एक मौसमी नज़ारा है जिसे बचाना जरूरी है।

- पक्षी विशेषज्ञ

सेशेल्स में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी

गणेश मंदिर में पूजा भी की, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत खाना हुआ

विक्टोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने तीन दिवसीय सेशेल्स दौरे के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विक्टोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रधानमंत्री ने अरुल मिहु नवशांति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद वह नई दिल्ली के लिए खाना हुआ।



इससे पहले भारत और सेशेल्स ने 19 बड़े समझौते और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इनमें सेशेल्स में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू करना, 1,250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट (लोन), साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति शामिल है। भारत ने सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी वाहन, 5 नौकाएं, 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी सौंपा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये समझौते किए गए।

मोदी ने कोको डी मेर पौधा अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों का एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तरकश और हड़दंग्राफिक सर्वे शिप आईएनएस इश्क भी परेड और समारोह का हिस्सा बनीं।

मोदी ने कोको डी मेर पौधा अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों का एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तरकश और हड़दंग्राफिक सर्वे शिप आईएनएस इश्क भी परेड और समारोह का हिस्सा बनीं।

175 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज: भारत ने सेशेल्स के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1651 करोड़) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा भारत ने सेशेल्स को भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस लेस्वार् गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस लेस्वार् सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को गिफ्ट किया। यह आजादी और भारत-सेशेल्स के बीच राजनयिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। उन्हें अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है।

मोदी सेशेल्स जाने वाले सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साल 1976 में सेशेल्स गई थीं। उसी साल सेशेल्स आजाद हुआ था। भारत ने सेशेल्स के स्वतंत्रता समारोह में नौसेना का युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि भी भेजा था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1981 में फिर सेशेल्स का दौरा किया था। उनकी यात्रा के बाद, लगभग 34 साल तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की यात्रा नहीं की थी।

अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर हमले रोकने पर राजी

आज कतर में फिर बातचीत होगी, होर्मुज से जहाजों का निकलना जारी रहेगा



तेहरान/वाशिंगटन डीसी। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक-दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका-ईरान में 17 जून को हुए समझौते के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर की वार्ता करेंगे। समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। हाल के दिनों में इसी जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और रडार ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जबकि ईरान ने जवाब में कुवेत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई है।

किए जाने वाले वादों को लागू करने पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोहा में बैठक होगी, लेकिन यह खबर सही नहीं है। बैठक तभी होगी, जब सभी जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी।

अमेरिका-ईरान के बीच तकनीकी बातचीत इस हफ्ते नहीं होगी: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। ईरान और अमेरिका के बीच रिवटजलैंड में 22 जून को पहले दौर की बातचीत हुई थी। पाकिस्तान और ओमान इसमें मध्यस्थ देश बने थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। ईरान और अमेरिका के बीच रिवटजलैंड में 22 जून को पहले दौर की बातचीत हुई थी। पाकिस्तान और ओमान इसमें मध्यस्थ देश बने थे।

होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की मीटिंग: ईरान और ओमान ने सोमवार को मस्कट में जाईंट होर्मुज कमेटी की पहली बैठक की। इस बैठक में होर्मुज स्ट्रेट को चलाने को लेकर चर्चा हुई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बताया कि उन्होंने ओमान के विशेष राजदूत अब्दुलअजीज अल हिनाई से मुलाकात की और होर्मुज से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। गरीबाबादी के मुताबिक दोनों देशों ने तेहरान-वाशिंगटन समझौता की आर्टिकल-5 के तहत होर्मुज के भविष्य के प्रबंधन पर विचार-विमर्श किया। बैठक में होर्मुज के संचालन, सुरक्षा और आगे की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दोनों पक्षों ने अपने विचार साझा किए।

ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा इंडियन डेलिगेशन: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का एक डेलिगेशन शामिल होगा। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसमें बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मोंगेंटा शामिल होंगे। इस महीने की शुरुआत में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि उनके शामिल होने की संभावना नहीं है।

ईरान बोला- कतर में फंसे 6 अरब डॉलर जल्द मिलेंगे: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि कतर में फंसी ईरान की 12 अरब डॉलर की राशि में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कॉम शहर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुए हलिया समझौते का बड़ा नतीजा है।

सपा-कांग्रेस पर जमकर बरसे

साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे, इसलिए जनता ने पंचर कर दी: सीएम योगी

पीलीभीत। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पतरासा कुंवरपुर गांव में 569.11 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने करीब ढाई हजार विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा और कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता ने साइकिल पंचर कर दी। अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे। कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब चंगा का माहौल है।



मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू परिवारों, गरीबों, दलितों और वंचितों की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति केवल तुष्टिकरण तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।

सपा-कांग्रेस ने वंचितों की कभी चिंता नहीं की: योगी-

निर्माणधीन रिसॉर्ट में दीवार ढही, तीन मजदूरों की मौत

जयपुर। जयपुर के चंदवाजी थाना क्षेत्र स्थित तालाबोड में निर्माणधीन द अरवली पैलेस रिसॉर्ट में सोमवार को हुए भीषण हदसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हदसे में रिकू, सविता और रामजी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों का निम्स अस्पताल में इलाज जारी है।

लंच टाइम ने टाला बड़ा हदसा: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हदसा दोपहर के भोजन के समय हुआ। उस वक़्त कई मजदूर खाना खाने के लिए साइट से बाहर गए हुए थे। प्रशासन का मानना है कि यदि हदसा कार्य के व्यस्त समय में होता तो जनहानि का आंकड़ा और अधिक हो सकता था।

स्टालिन ने कर दिया बहुत बड़ा दावा

तमिलनाडु में गिरने वाली है थलपति विजय की सरकार

नई दिल्ली। तमिलनाडु में सीएम थलपति विजय की सरकार को लेकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। स्टालिन ने कहा है कि विजय की सरकार जल्द ही गिर सकती है और राज्य में महीने आए चुनाव परिणामों के बाद सत्ता से बाहर होने वाली मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (डीएमके) के अध्यक्ष स्टालिन ने रविवार रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही हैं। उन्होंने इस दौरान राज्य में बहुत जल्द मध्यावधि चुनाव होने की भविष्यवाणी भी की।

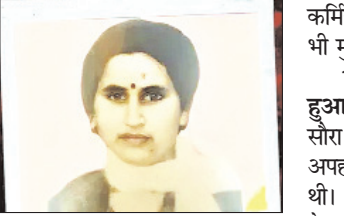
स्टालिन ने दावा किया कि अग्निप्रेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेंकट कन्नम सरकार के पास बहुमत नहीं है और अगले 3 से 6 महीनों के भीतर राज्य में विधानसभा चुनाव दोबारा हो सकते हैं।



सरला भट्ट हत्याकांड: 35 साल बाद यासीन मलिक समेत 5 आतंकियों पर चार्जशीट

तिहाड़ से चलेगा मुकदमा

श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर के सबसे जघन्य अपराधों में शामिल कश्मीरी हिंदू नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या मामले में 35 वर्ष बाद बड़ी जांच कार्रवाई हुई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआई) ने अपनी जांच में जेकेएलएफ के पांच आतंकवादियों की संलिप्तता पाई है और सगठन के पूर्व कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक तथा उनके सहयोगी खुशीद अहमद चाल्कू के खिलाफ 737 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है। एसआई के अनुसार, मामले में पांच आतंकवादियों-यासीन मलिक, अब्दुल हमीद शेख, गुलाम मोहम्मद टपट्टू, मोहम्मद यूसुफ उर्फ इदरीस और खुशीद अहमद चाल्कू-की भूमिका सामने आई है। इनमें अब्दुल



हमीद शेख, गुलाम मोहम्मद टपट्टू और मोहम्मद यूसुफ की पिछले वर्षों में मृत्यु हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि खुशीद चाल्कू करीब दो दशक पहले पाकिस्तान भाग गया था। यासीन मलिक और चाल्कू के विरुद्ध उद्धोषणा (प्रोक्लेमेशन) की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। यासीन मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा वे रुबैया सईद अपहरण कांड और 1990 में भारतीय वायुसेना के चार

कर्मियों की हत्या से जुड़े मामलों में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। 19 अप्रैल 1990 को बरामद हुआ था शव: एसकेआईएमएस, सौरा में कार्यरत नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। 19 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के मल्लाबाग क्षेत्र से उनका गोलियों से छतनी शव बरामद हुआ था। यह घटना कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर के सबसे निर्भय अपराधों में गिनी जाती है और इसे कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौर की प्रतीक घटनाओं में भी माना जाता है। 34 साल बाद एसआई के सौंपी गई जांच: आतंकवाद के चरम दौर में भय और गवाहों के सामने न आने के कारण यह मामला दशकों तक अन्सुलझा रहा। 18 मार्च 2024 को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर इसकी जांच एसआई के सौंपी गई।

केरल में सियासी दंगल: बीजेपी-कांग्रेस पार्षदों में भिड़ंत

हुई तू-तू में-में, पार्षद की कुर्सी पर बवाल

तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में सोमवार को परिषद की बैठक के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट हुई। वाइब्रोकोनम वार्ड से भाजपा पार्षद सुगथन के इस्तीफे की मांग को लेकर एलडीएफ पार्षदों ने प्रदर्शन शुरू किया था। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसने देखते ही देखते हाथपाई का रूप ले लिया।



विवाद की जड़ में क्या? : इस पूरे विवाद की जड़ भाजपा पार्षद सुगथन की गिरफ्तारी है। सुगथन को बीते 10 जून को केरल असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (केएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुगथन पर एक मंदिर उत्सव के दौरान कथित हमले का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। सुगथन पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तारी के वक्त हुआ था भारी बवाल, पुलिस ने चलाई थी गोली 10 जून को जब पुलिस भाजपा पार्षद सुगथन को गिरफ्तार करने पहुंची, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम को बुरा किया था। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी। इस हंगामे के बाद पुलिस ने सुगथन और चार अन्य लोगों के खिलाफ लोक सेवकों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का एक नया मुकदमा भी दर्ज किया है।

सीबीएसई और वेदांत में फिर ठनी

री-इवैल्यूएशन के नंबरों पर बवाल, बोर्ड ने बताया झूठा तो छात्र ने पूछा तीखा सवाल

नई दिल्ली। सीबीएसई और बारहवीं के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव के बीच नंबरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बेहद गंभीर और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सफल है तो सीबीएसई ने वेदांत के दावों को हफ्तद झूठ करार दिया, जिसके बाद वेदांत ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए बोर्ड की पूरी थ्योरी पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नए विवाद की शुरुआत सीबीएसई की तरफ से जारी एक आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद हुई। बोर्ड ने 28 जून को साफ किया कि बारहवीं कक्षा के मार्क्स वैरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के 99.7 फीसदी से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी नोट में सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव के उन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और संघर्ष झूठ बताया, जिसमें छात्र ने कहा था कि री-



इवैल्यूएशन के बाद उसके फिजिक्स के नंबरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान वेदांत के फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स 35 से बढ़कर 44 हो गए, यानी सीधे 9 नंबरों का फायदा हुआ। इसके अलावा, मैथमेटिक्स में उसके नंबर 46 से 47 (1 नंबर की बढ़ोतरी) और कंप्यूटर

साईंस में 61 से 62 (1 नंबर की बढ़ोतरी) हुए। बोर्ड का कहना है कि तीनों विषयों को मिलाकर छात्र के कुल 11 नंबर बढ़े हैं। वेदांत का पलटवार: सीबीएसई के इस बयान के बाद वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया। वेदांत ने बोर्ड को टैग करते हुए लिखा, फिजिक्स में जो 9 नंबर बढ़ने की बात आप कह रहे हैं, वे री-इवैल्यूएशन के जरिए नहीं बढ़े हैं। वो मेरे असल नंबर हैं जो आपने मुझे पहले इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि आपकी तरफ से मेरी आंसर शीट ही बदल दी गई थी। री-इवैल्यूएशन के पोर्टल से तो मेरे सिर्फ दो ही नंबर बढ़े हैं, एक कंप्यूटर साईंस में और एक मैथ्स में। वेदांत ने सीबीएसई के आरोपों पर तीखा सवाल दागते हुए पूछा कि यह बात भला झूठ कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि

फिजिक्स के 9 नंबर री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने से पहले ही ठीक कर दिए गए थे। छात्र का तर्क सीधा है कि 9 नंबरों का इजाफा उस वक़्त हुआ जब सीबीएसई ने अपनी गलती मानी कि उसकी आंसर शीट किसी दूसरे छात्र के साथ बदल गई थी। असली री-इवैल्यूएशन से तो सिर्फ गणित और कंप्यूटर साईंस में एक-एक नंबर ही बढ़ा है। इस पूरे मामले पर वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने भी मीडिया से बात की और बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई। सिद्धांत ने साफ कहा कि वेदांत का ओरिजिनल फिजिक्स थ्योरी स्कोर 44 था, न कि 35। इसलिए बोर्ड का यह कहना कि उसका स्कोर 35 था, पूरी तरह गलत है। सिद्धांत ने कहा कि यह बेहद खेदजनक स्थिति है।

चीन ने फिर की चालबाजी, तीस्ता डील पर भारत की चिंताओं को किया दरकिनार

बोला- तीसरा देश दखल न दे

नई दिल्ली। भारत की गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना को अपना पूरा समर्थन दोहराया है। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ शब्दों में कहा कि चीन और बांग्लादेश का यह आपसी सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना नहीं बनाता है, इसलिए इसे किसी तीसरे देश के प्रभाव या दखल से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। चीन ने बताया रोजगार और आजीविका का प्रोजेक्ट



भारत की आपत्तियों का जवाब देते हुए चीन के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इसे आम लोगों से जुड़ा प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि तीस्ता नदी का व्यापक परिचालन और जीर्णोद्धार एक आजीविका परियोजना है, जिसे बांग्लादेश सरकार बहुत ज्यादा महत्व देती है। चीन इस परियोजना का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, उसे करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे नवीकरियां लगातार बढ़ रही हैं।

कहा कि चीन, बांग्लादेश के साथ अपनी विकास रणनीतियों को और मजबूत करने और व्यापार, जल संरक्षण और जन-जीवन से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। बांग्लादेश और चीन के बीच नया समझौता: पहली बार होगी तकनीकी स्टडी- बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बताया कि दोनों देशों के विशेषज्ञ अब पहली बार इस परियोजना पर एक गहन तकनीकी अध्ययन करेंगे। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं। अगर यह स्टडी प्रोजेक्ट देश के सही रहेगी है, तो चीन इस योजना को पूरा करने के लिए हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। नदियों के प्रबंधन को लेकर छाका और बीजिंग के बीच नवीकरियां लगातार बढ़ रही हैं।